MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS — *Contd.*

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने 31 जनवरी को अपना अभिभाषण दिया। मई, 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद यह उनका चौथा अभिभाषण था, इसलिए स्वाभाविक है, भारत के लोगों की यह अपेक्षा है कि सरकार अपने कार्यकाल का, जिसके 34 महीने होने जा रहे हैं, उसका लेखा-जोखा देगी, उसका हिसाब बताएगी, पर यह अभिभाषण भी पहले के तीन अभिभाषणों की तरह वायदों और घोषणाओं से भरा हुआ है। इसमें कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, केवल सरकार के दावे हैं। सरकार ने यह बताने की चेष्टा नहीं की कि उपलब्धियां क्या हुई हैं। 2014 में, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब यह सरकार आई थी, तो यह वायदों की सूनामी पर आई थी, हिन्दुस्तान के लोगों को सब्ज़बाग और सपने दिखा कर आई थी। आपने हिन्दुस्तान के किसान के साथ रोजगार का वायदा किया था, आपने MSP बढ़ाने की बात कही थी, आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, आपने 100 Smart Cities बनाने की बात की थी। सूची बड़ी लंबी है, मैं सब बातें नहीं दोहराना चाहता, हमारे साथी, सदन के और लोग उस पर कह चुके हैं। मेरा प्रश्न है कि जब प्रधान मंत्री जी उत्तर दें, तो बताएँ कि आपका एक साल में दो करोड़ रोजगार देने का वायदा था, ढाई साल में 5 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। जमीनी हकीकत अलग है। उपसभापति महोदय, रोजगार टूटे हैं, रोजगार पैदा नहीं हुए हैं। ये लाखों में टूटे हैं और अब करोड़ों में टूटे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।

आपका दूसरा वायदा था किसान की MSP बढ़ाने का, उसका क्या हुआ? आपने उसे क्यों नहीं बढ़ाया? खास तौर पर जब आप खुद कहते हैं कि दो साल तक सूखा रहा, बुवाई नहीं हुई, फसलें खराब हो गईं। भारत के संपन्न राज्यों के अन्दर किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। पंजाब जैसे सूबे में किसान आत्महत्या कर ले! हरियाणा में चले जाइए, आत्महत्या, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और प्रधान मंत्री कहते हैं सब अच्छा है! ये आपके अच्छे दिन हैं! तमिलनाडु, भारत का कोई राज्य नहीं छूटा। आपके हृदय में कोई संवेदना नहीं है। आप उनकी पीड़ा को नहीं समझना चाहते हैं। आप केवल वाहवाही लूटना चाहते हैं, बिना कोई काम किए, बिना कोई रिजल्ट दिखाए। यह मेरा आपसे सीधा प्रश्न रहेगा।

एक वायदा आपका बड़ा वायदा था। प्रधान मंत्री कोई मौका नहीं छोड़ते, जब भ्रष्टाचार और काले धन की बात न करते हों, ब्लैक मनी की बात न करते हों। कल भी कहा, रोज कहते हैं, जरूर कहें, किसने उनको रोका है? पर वायदा तो उनका था कि विदेशों में 1,86,000 करोड़, यह calculation किसने की, मुझे नहीं मालूम, इनके बीजेपी की कोई टास्क फोर्स बनी थी। ...(**व्यवधान**)... टोका-टोकी मत करिए। *, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या बताई, समझ में नहीं आया, संख्या सुन कर दिमाग घूम गया और कहा कि पैसा वापिस आएगा और हर हिन्दुस्तानी के खाते में कम से कम 15 लाख रूपए जमा कराऊँगा। ...(**व्यवधान**)... आप क्यों बोलते हैं? ...(**व्यवधान**)... सर, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप लोग टोका-टोकी मत करें। ...(**व्यवधान**)... छोड़िए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... सर, अगर ये मेरा समय खराब करेंगे, तो उसे मेरे समय से काट दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः ठीक है, ठीक है। आप बैठिए, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री आनन्द शर्माः इस पर प्रधान मंत्री बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप बैठिए, आप बैठिए। The Prime Minister would reply. Don't worry. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आपके सक्षम, मजबूत प्रधान मंत्री इस पर बोलेंगे, तो आप क्यों बीच में टोका-टोकी करते हैं? उनको आ जाने दीजिए, वे जवाब दे देंगे। ...(**व्यवधान**)...

विधि और न्याय मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, इन्होंने * का नाम लिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. The name * is expunged.

श्री आनन्द शर्माः नाम मैंने नहीं लिया है, वहां से आया है। मैंने दोहराया, यह आया वहां से। चलिए, छोड़िए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay.

श्री आनन्द शर्माः सर, मुझे आपके माध्यम से यह कहना है कि इस अभिभाषण के अन्दर और प्रधान मंत्री हर भाषण के अन्दर प्रभावशाली, वजनदार शब्दों का प्रयोग करते हैं। सत्ता में आने से पहले उन्होंने अपना दर्शन दिखाया। 5 Ts - tradition, technology, talent, tourism and trade. मुझे इसमें कोई नई चीज़ नहीं पता लगी है, क्योंकि सब चीज़ें सदियों से हो रही हैं। पर्यटन भी सदियों से हो रहा है, व्यापार भी हो रहा है और परम्पराएं भी सदियों पुरानी हैं। चलिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यह उनकी सोच है। उसके बाद उन्होंने तीन 'Ds' बताए – Democracy, Development and Demography. ये तीनों हमको पहले ही पता थे। पूरे देश और पूरी दुनिया को पता है कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या कितनी है और कितने लोग 35 बरस की उम्र के नीचे के हैं। भारत प्रजातंत्र है, यह सबको पता है और हर देश development चाहता है, यह भी सबको पता है, लेकिन धन्यवाद, आपने हमें पांच 'Ts' और तीन 'Ds' दे दिए। उसके बाद यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। 'Stand-up India' दिया, क्या अभी तक भारत सो रहा था? 'Start-up India' दिया, क्या हिन्दुस्तान की गाड़ी बंद हो गई थी? 'Digital India', 'Techindia' ...(*Interruption*)... देखिए, आप बीच में मत बोलिए।...(**व्यवधान**)... आप सुनिए।

मेरा फिर आपसे आग्रह है कि आप सुनिए। प्रधान मंत्री में तो सहनशीलता नहीं है, आप तो सहनशीलता रखिए। मुझे आपसे यह कहना है कि ये सारे के सारे शब्द अंग्रेज़ी के हैं, इनका जो विज़न है, वह हिन्दी या संस्कृत में नहीं है। तीन 'Ds', पांच 'Ts' के बाद 'Digital India', 'Stand-up India', 'Start-up India', 'Techindia', ये सब अंग्रेज़ी में हैं। भारत में तो technology की क्रांति पहले ही आ चुकी थी। सबसे पहले इसके बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने सोचा था और श्री राजीव गांधी जी इसको आगे लेकर चले थे। Information Technology के मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाए हैं, आपको मालूम ही है कि यहां पर Technology Mission पहले ही कायम हुए थे। उस वक्त हिन्दुस्तान के अंदर हड़ताल हुई थी, 'भारत बंद' की आवाज़ उठी थी, इन सब बातों के बारे में सारा सदन जानता है। तब

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री आनन्द शर्मा]

तो right, left और center एक साथ हो गए थे कि राजीव गांधी जी यहां से नौकरियों को खत्म कर देंगे, बैंकों में केवल कंप्यूटर काम करेंगे। ...(**व्यवधान**)... उस वक्त तो वह नहीं हुआ था, पर अब वे हालात जरूर पैदा होंगे, जो आप करने जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

मुझे एक चीज़ गंभीरता के साथ कहनी है। देश आगे बढ़ेगा तो भारी भरकम शब्दों से नहीं बढ़ेगा, वह बड़ी सोच से बढ़ेगा, नीति से बढ़ेगा, रूपरेखा से बढ़ेगा। मैंने दुनिया के अंदर कभी कोई बड़ा परिवर्तन महज शब्दों से होते हुए नहीं देखा है।

उपसभापति जी, एक बात और है, जिसे हम हर रोज़ सुनते हैं, वह मानसिकता का प्रश्न है। वह मानसिकता क्या है, — 'पहली बार भारत में यह हो रहा है'। पहली बार विश्व के अंदर भारत का सम्मान हो रहा है, पहली बार भारत की पहचान हो रही है, पहली बार भारत की प्रगति हो रही है, पहली बार भारत का व्यापार बढ़ रहा है, हालांकि सच यह है कि व्यापार टूट गया है। यह मानसिकता कोई स्वस्थ मानसिकता नहीं है। अब आपमें से किसी को मैं कष्ट तो नहीं देना चाहता कि प्रधान मंत्री से कहिए कि वे इस बात को बोलना बंद कर दें, पर हम तो कह सकते हैं, क्योंकि हम तो प्रतिपक्ष के लोग हैं। हम रोज़ उनकी गाली सुनते हैं, इसलिए हम इतना निवेदन तो कर ही सकते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए 'पहली बार' शब्द का प्रयोग मत कीजिए। पहले भी बहुत कुछ हो चुका था।

कल हमारे सदस्यों ने बताया, वहां कहा गया कि हिन्दुस्तान अंतरिक्ष शक्ति बन गया है, परमाणु शक्ति बन गया है, लेकिन हिन्दुस्तान पहले ही अंतरिक्ष शक्ति और परमाणु शक्ति बन चुका था। इन्दिरा गांधी जी के समय में पोखरण का विस्फोट हुआ था। 1975 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष में चला गया था। भारत स्पेस शक्ति बने ...(**व्यवधान**)... हम उसके बाद की बात भी आपको बताएंगे, आप बीच में ऐसा क्यों करते हैं? ...(**व्यवधान**)... पहले ही वह शक्ति बन चुका था। आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि हिन्दुस्तान कहां तक पहुंच चुका था। कल चंद्रयान का जिक्र हुआ, मंगलयान का जिक्र हुआ। माननीय प्रधान मंत्री जी, प्रधान मंत्री बन गए, इस पर इन्होंने बड़ी तालियां बजाईं, अच्छा किया। बेहतर होता आप यह स्वीकार कर लेते कि हिन्दुस्तान को Stand-up या wake-up होने की जरूरत नहीं है, पहले ही वह चल रहा था और तभी आज यहां तक पहुंच गया है, लेकिन आपने यह बात नहीं कही, आपने यह विनम्रता नहीं दिखाई, यह दरियादिली नहीं दिखाई।

मुझे एक चीज़ कहनी है। यह सही है कि आपकी सरकार ने कुछ पुराने इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया है, जैसे 'आधार' है। यहां से वहां जाने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ है। जब आप यहां थे, तब तो 'आधार' गलत था, Direct Benefit Transfer (DBT) गलत था। आप ही उस समय यह कहते थे, लेकिन आज ठीक है, आज आप ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं।

'स्वच्छ भारत अभियान' एक अच्छा काम है। इक्कीसवीं सदी में भारत में स्वच्छता न हो, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा, लेकिन एक जमीनी हकीकत यह भी है कि पहले भी यह अभियान था, जिसका नाम 'निर्मल भारत अभियान' था, जिसका नाम बदल कर आपने 'स्वच्छ भारत अभियान' कर दिया है। जन-धन खाते खुलवाने के लिए आपको बधाई। उससे पहले जब माननीय राष्ट्रपति जी, वित्त मंत्री थे, उसके बाद श्री पी. चिदम्बरम जी थे, तो उन्होंने, जिसे चिदम्बरम जी 'no frills account' कहते हैं, जिसे Basic Account Deposit Scheme भी कहते हैं, उसमें 13 करोड़ खाते

खुले थे। ...(**व्यवधान**)... अच्छा हुआ है। देखिए, अगर आप ऐसा करें, तो ठीक नहीं है। उसमें भी खुले थे। आपके समय में भी 26 करोड़ खुले हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः वह अंग्रेजी में था। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः आपके समय में भी 25-26 करोड़ एकाउंट खुले हैं। इस बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से 80 परसेंट या शायद इससे ज्यादा dead accounts हैं, ज़ीरो बैलेंस एकाउंट्स हैं, जिसके नाम पर खाता है, उसे नहीं पता। ...(**व्यवधान**)... देखिए, नया मुल्ला कभी-कभी नमाज़ ज्यादा पढ़ता है। मेरे दोस्त रहने दो। ...(**व्यवधान**)... रहने दो, यह ज्ञान अपने पास रखो। ... (**व्यवधान**)... ठीक है। ...(**व्यवधान**)... Sir, the Minister is interrupting. He should be asked to conduct himself as a Minister.

THE MINISTER OF STEEL (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): He should also not give the wrong figures. If he does not have the correct figures, he should not quote them. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः भैया, इससे कुछ नहीं होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंहः भैया कुछ नहीं होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः यदि भैया कुछ नहीं है, तो जब प्रधान मंत्री आएं, तब आप मुझे टोकना, तो वे आपको अच्छा पोर्टफोलियो दे देंगे। जब वे आ जाएं, तब बात करना। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति महोदय, पहले तो आप ये नोटिस लें कि मंत्री महोदय व्यवधान डाल रहे हैं, उन्हें रोकें। दूसरी बात यह है कि जो मेरा ये समय काट रहे हैं, वह समय मैं ज्यादा लूंगा, यह मेरा आपसे आग्रह है।

सर, अब मुझे एक बात कहनी है कि अगर प्रधान मंत्री विनम्रता और शालीनता से विपक्ष से और सबसे बात करें, सबकी बात सुनें, तो उससे उनके पद की गरिमा बढ़ेगी। दम्भ और अहंकार से, गुस्से और डांटने से, इतने बड़े पद की गरिमा बढ़ती नहीं, बल्कि कम होती है।

महोदय, अभिभाषण में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। मैं पैरा 79 का जिक्र करता हूं। इस पैरा के प्रारम्भ में और आखिर में भी कहा गया है कि 'सबका साथ और सबका विकास', 'चर्चा, संवाद, समन्वय, संवेदना'। मैं इन सबका समर्थन करता हूं। कौन नहीं चाहता कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, कौन नहीं चाहता कि चर्चा और संवाद न हो। यह तो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। वाद, विवाद और संवाद होता है। यह कोई नई बात नहीं है और हम सब इसके पक्ष में हैं। यह हम सबको करना चाहिए, भले ही हमारी अलग-अलग राय हो, लेकिन मुझे दुख के साथ यह कहना है कि आपकी सरकार की सोच और काम करने का तरीका, इसके बिलकुल विपरीत है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने अपने से पूर्व प्रधान मंत्रियों के योगदान को और उनकी सोच को स्वीकार नहीं किया है। बेहतर होता, उनके काम को छोटा न दिखाते, नगण्य न दिखाते और यह स्वीकार करते कि मेरे से पहले और भारत की आज़ादी के बाद, जितने प्रधान मंत्री रहे, वे भी देश के प्रति समर्पित थे और उन्होंने भी देश के लिए काम किया। पं. जवाहरलाल नेहरू, मुझे मालूम है कि आप उनका नाम स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि वे स्वतंत्रता

[श्री आनन्द शर्मा]

संग्राम की अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। अंग्रेजों की जेल में सबसे ज्यादा समय पं. जवाहरलाल नेहरू ने काटा था। उनके 125 साल हुए, लेकिन आपने उनका नाम नहीं लिया। यह इतिहास का सम्मान नहीं है। वे तो आपसे सम्मान मांगने नहीं आ रहे हैं। आपसे उनके लिए सम्मान मांगने कोई नहीं आ रहा है। वे तो अपनी कुरबानी कर के दुनिया से चले गए।

महोदय, इसलिए मैं कहता हूं कि पं. जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने हिन्दुस्तान के लिए शहादत दी, क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है? उसके बाद कई प्रधान मंत्री आए। कई दलों के आए। श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री रहे। मैंने उनका ज़िक्र किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, डा. मनमोहन सिंह जी रहे। क्या हो जाता, यदि ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः श्री नरसिंहराव जी भी थे।

श्री आनन्द शर्माः श्री नरसिंहराव जी भी रहे। मुझे उनका नाम याद दिलाने के लिए धन्यवाद। उस समय आर्थिक सुधार हुए थे। वह उनका युग था, लेकिन मैं कह रहा हूं, आपने मुझे याद कराया, परन्तु दुख तो इस बात का है कि मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री जी का नाम आपको याद कराना पड़ रहा है।

श्री रवि शंकर प्रसादः नहीं, वे तो हमारे पास हैं।

श्री आनन्द शर्माः क्या इन सब प्रधान मंत्रियों की कोई उपलब्धि नहीं थी ? मुझे आज आपसे एक चीज कहनी है और उसे आप गौर से सुनें। पिछले साल इंदिरा जी पर एक टिप्पणी हुई। पहले वह टिप्पणी हुई थी प्रधान मंत्री जी द्वारा 19 नवंबर को, जिस दिन इंदिरा जी की anniversary थी, उनकी सालगिरह थी और वह भी 100वीं। उन्होंने demonetization के संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में कहा कि इंदिरा जी इसके खिलाफ थीं और 1978 में या उससे पहले जब माननीय वाई. बी. चव्हाण जी वित्त मंत्री थे, 1978 में तो आपकी सरकार थी। ...(**व्यवधान**)... 1971 में बंगलादेश आजाद हुआ था, उसे याद करते तो बेहतर होता। इंदिरा जी के पास जब तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री वाई. बी. चव्हाण गए - He went with his proposition कि demonetization कर लें, लेकिन इंदिरा जी ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत, क्या हमें आगे चुनाव नहीं लड़ना? अब वे दोनों तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, इंदिरा जी भी चली गईं और वाई. बी. चव्हाण जी भी नहीं रहे, लेकिन लिखा हुआ किसका है, प्रधान मंत्री जी जरा गहराई से सोचिए, गम्भीरता से, जो उस वक्त के वित्त मंत्री के Executive Assistant थे। मैंने कभी नहीं सुना, हम भी सरकार में रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हम भी अपने प्रधान मंत्री से मिलने जाते थे, क्या इंदिरा गांधी जी से उनके वित्त मंत्री मिलने जाएं तो क्या इंदिरा गांधी जी उस बैठक में Finance Minister के Assistant को भी साथ में बिठाएंगी? मैं आपसे सवाल करता हूं। आप सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। आप प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते हैं। वे आपसे बात करते हैं, आप उन्हें अपनी बात बताते हैं, क्या आपके पी.ए. या पी.एस. भी साथ में पी. एम. से मिलने जाते हैं — यह मेरा आपसे सवाल है। केवल उसे आधार बनाकर इतनी बड़ी बात करना ...(**व्यवधान**)... इतनी बड़ी टिप्पणी करना ...(**व्यवधान**)... यह बड़े दुःख का विषय है।

अब मुझे उससे आगे चलकर...(**व्यवधान**)... मुझे तो कुछ क्षण का समय मिलता है, उधर तो सारा समय रहता है। मुझे प्रधान मंत्री जी के लिए कहना है, वह तो आएंगे नहीं, आप उन्हें बता देना, सुना देना किः—

"तुम्हारी शान बढ़ जाती, यह रूतबा बढ़ गया होता,
कहा जो अपनी शान में, किसी और की शान में भी कहा होता।"

...(**व्यवधान**)... मुझे आपसे कहना है कि जहां आप संवाद की बात करते हैं, सहमति की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं तो आपकी मानसिकता विपक्ष को बदनाम करने की रहती है। आपकी मानसिकता टकराव की होती है। आप कोई मौका नहीं चूकते। देश में, विदेश में, जहां भी जाते हैं, विपक्ष को बदनाम करते हैं। अपने से पूर्व सरकारों की बुराई करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हमने कई बार आग्रह किया कि कम-से-कम देश के बाहर तो ऐसी बातें बंद कर दीजिए। पहले तो मई, 2014 के बाद ही यह बंद हो जाना चाहिए था। आपकी सरकार बन गई, अब इस बात को खत्म करें, परन्तु आपने एक ऐसी गलत परम्परा डाल दी है, अच्छा समझकर, लोगों को गुमराह करने के लिए तो अच्छा है, परन्तु भारत के प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह परम्परा अच्छी नहीं है। आप बात भी बड़े गज़ब की कहते हैं।

अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रचार में सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, प्रधान मंत्री जी भी रोज़ जाते हैं और रोज़ जाएं। वहां बड़े जोश से बोलते हैं और खूब बोलें, परन्तु उन्होंने कहा कि जो विरोधी हैं, वे स्कैम हैं। नए शब्द बनाने में शायद उन्हें आनन्द आता है, अच्छे लगते हैं, जैसा मैंने पहले कहा — 3 डी, 5डी आदि — सब कुछ है, लेकिन क्या एक राजनैतिक दल, समाजवादी पार्टी, जिसकी यू.पी. में सरकार है, सी फॉर कांग्रेस, जिसने हिन्दुस्तान की आजादी का संघर्ष लड़ा, कुर्बानियां दीं और आजादी के बाद हमारे दो-दो प्रधान मंत्री शहीद हुए, तीसरा कौन — एक मुख्य मंत्री और चौथी एक पूर्व मुख्य मंत्री, जो दलित हैं, इन सबको देश के प्रधान मंत्री जी ने क्या परिभाषा दी — स्कैम। कोई और कहता तो मुझे आपत्ति नहीं थी। उनके लिए ऐसा कहना, ऐसी भाषा, ऐसी शैली का प्रयोग करना, मैं इसकी निन्दा करता हूं। यह अच्छी बात नहीं है कि इस तरह से प्रजातंत्र में विरोध पक्ष को आप अपमानित करें। कलंकित करने, बदनाम करने का कोई मौका आप नहीं छोड़ते हैं। यह दिखाना कि समूचा विपक्ष भ्रष्ट है, काले धन का समर्थक है, केवल आप, भारतीय जनता पार्टी और आपके माननीय प्रधान मंत्री, आप साधु-संत समाज हैं, सारे बुरे लोग इस तरफ बैठे हुए हैं। मेरा आपसे सवाल है, काले धन के खिलाफ हिन्दुस्तान में लड़ाई चल रही है, खूब चले, पर जनाब, इनके पास जो प्रचंड साधन हैं, प्रचार-तंत्र हैं, वह पैसा जो खर्च होता है, बड़ी-बड़ी रैलियों के लिए हजारों बसें जाती हैं, हेलिकॉप्टर चलते हैं, जहाज चलते हैं, यह कौन-से फकीर बैंक से पैसा आ रहा है, कौन-से पवित्र कुंड से यह पैसा आ रहा है, कौन-से चेक से यह पेंमेंट हो रही है? ज़रा हिन्दुस्तान को बताओ तो! पता तो लगे असली बात! हम तो चाहते हैं, अब थक गए और कहना बन्द कर दिया, लेकिन कभी आएँ, सुनें और फिर उसका जवाब दें, पर वह आपको स्वीकार्य नहीं है।

उपसभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि यह दिखाना कि केवल यह सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता चाहती है, transparency and accountability, this is wrong, and I reject it. आपकी सरकार का पहला अभिभाषण वर्ष 2014 का था, जिसमें आपने कहा था कि लोकपाल बनेगा। वह लोकपाल कहां है? 130 करोड़ लोगों के देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको

[श्री आनन्द शर्मा]

लोकपाल बना दो! कानून तो हमने बनाया था, बुरे तो हम हैं। आरटीआई हम लाए थे, उसको dilute ये कर रहे हैं। इस देश में Money Laundering Act भी बना। यह कहना कि आज से पहले कुछ हुआ ही नहीं, पहली बार हो रहा है! पहली बार यह भी हुआ कि इन्होंने यह वर्ष 2014 में कहा और अब तीन बरस होने जा रहे हैं, मगर हिन्दुस्तान अभी भी लोकपाल की तलाश कर रहा है कि कहां गए लोकपाल? आज प्रधान मंत्री आकर इस पर ज़रा बताएँ, जवाब दें।

महोदय, प्रजातंत्र में विचार अलग-अलग हैं, मत अलग-अलग हैं, विचारधाराएँ अलग हैं। राजनैतिक विरोध होता है, विचारधाराओं का टकराव होता है, व्यक्तियों का टकराव नहीं होना चाहिए। राजनैतिक विरोधी को निजी शत्रु मानना, यह गलत बात है, पर प्रधान मंत्री कहते हैं। भारत की तस्वीर इससे सुधरेगी नहीं कि हम एक-दूसरे को शत्रु के रूप में देखना शुरू कर दें। चुनाव में होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रधान मंत्री बोलें, तो उनका एक-एक शब्द देश और दुनिया सुनती है। उन्होंने कल कह दिया, उत्तराखंड के भूकम्प की याद दिलाई कि उत्तराखंड में भूकम्प आ गया। चाहे उन्होंने मज़ाक के लहजे में बोला, पर वह अच्छा मज़ाक नहीं था। ...(**व्यवधान**)...

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंहः नुकसान तो कुछ हुआ नहीं? ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः देखिए, ये बार-बार बोल रहे हैं। या तो ये बोल लें या मैं बोल लूँ। अभी वे आ जाएँ, तब टोका-टोकी करो, आपका पोर्टफोलियो बदलेंगे। ...(**व्यवधान**)... मुझे यह कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के वाइस प्रेजिडेंट, राहुल गांधी जी के बारे में कहा। अब इससे एक चीज़ पता लगती है कि राहुल गांधी जी का नाम इनको रोज़ याद आता है और वे रोज़ बोल रहे हैं। यह अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, पर एक बात की निन्दा करूँगा। उत्तराखंड के लोगों को भूकम्प की याद मत दिलाएँ, उत्तराखंड में हज़ारों लोग मरे थे, उत्तराखंड में सैकड़ों मन्दिर टूटे थे, वहां लोग बह गए थे और उस उत्तराखंड को सम्भालने में वर्षों लग गए। कटाक्ष करते हुए हम राजनैतिक सम्वाद को इतना न गिराएँ कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, उनको पीड़ा हो। यह आप मत करें और आगे से ऐसा न कहें। उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि देश के प्रधान मंत्री जब भी कहीं बोलें, तो थोड़ी-सी शालीनता रखें और सम्वेदनशील रहें कि इसमें लोगों की क्या भावनाएँ जुड़ी हैं। इसको ध्यान में रखें, तो बेहतर होगा।

प्रधान मंत्री ने एक और चीज़ कही कि मुझसे विपक्ष डरता है। आपसे पूरा देश डरता है। ...(**व्यवधान**)... आपने कहा कि विपक्ष को मुझसे डर लगता है। ...(**व्यवधान**)... अब वे यहां आएँ, आप उनको बुलाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः ऐसा कब कहा? ...(**व्यवधान**)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): शर्मा जी, आप ऐसी बात मत कहिए, जिसमें न कोई तर्क हो, न तथ्य हो। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः ऐसा उन्होंने यूपी की एक रैली में कहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः रैली का ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दे दूँगा, वह मेरे पास है। यह परसों के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में एक पूरे बॉक्स में छपा है कि प्रधान मंत्री ने कहा, "विपक्ष को मुझसे डर लगता है।" भाई, मान लिया आपसे डर लगता है, क्योंकि आप सारी एजेंसीज़ का दुरूपयोग करते हो। सीबीआई का, ईडी का, कुछ छोड़ा नहीं आपने। आपसे डर किस को नहीं लगता? आप जब भी मुंह खोलते हैं, गुस्से की बात करते हैं, पर आप सब भी मानेंगे नहीं, हम विपक्ष में बोल तो लेते हैं, लेकिन आपके साथ भी वही हो रहा है। मैं क्या बोलूं आपको, आप समझें या न समझें, वह अलग बात है।

उपसभापति महोदय, 8 नवम्बर के दिन रात के समय हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने एक बड़ी नाटकीय घोषणा की । 86 प्रतिशत भारत की करेसी 15 लाख करोड़ रूपया रद्द कर दिया। क्या कह कर किया? यह कहा कि आज के बाद यह रद्दी का कागज का टुकड़ा है। इसके क्या कारण दिए, तीन कारण हैं, काले धन को समाप्त करना है, नकली नोट या counterfeit currency करेसी को खत्म करना है और टैरर फंडिंग को समाप्त करना है। हमने भी सत्य कहा कि तीनों काम अच्छे हैं। हम भी चाहते हैं कि काले धन को खत्म करो, भ्रष्टाचार को खत्म करो, counterfeit currency खत्म करो और टैरर फंडिंग खत्म करो। लेकिन ये तीनों बातें गलत निकलीं। पहले 86 प्रतिशत पैसा 15 लाख करोड़ जो भारत के किसान का था, मजदूर का था, कर्मचारी का था, गृहिणी का था, रेहड़ी-खोमचे वाले का था, छोटे दुकानदार का था, हिन्दुस्तान की जनता के पैसे को आपने काले धन के खिलाफ लड़ाई कह कर पूरे देश की जनता को कलंकित किया। क्या भारत का अर्थतंत्र काले धन पर चलता था? पूरी दुनिया में क्या संदेश गया? प्रधान मंत्री जी, क्या हिन्दुस्तान, जो बड़ी इकोनॉमी है, जो आगे बढ़ रहा है, वह काले धन पर आगे बढ़ रहा है, सब लोगों के पास काला धन है? जो गरीब का पैसा पांच सौ रूपया, एक हजार रूपया आपने उसको खत्म किया और आप यह नहीं हिसाब देते कि उसमें से कहां गया वह पैसा, कितना पैसा वह वापस आया? 30 दिसम्बर को आपने नोट की बदली खत्म कर दी थी। अब 30 दिसम्बर के बाद आज तक गिनती हो रही है। You want India to become digital! The Finance Minister has also come. Kindly enlighten us – and the Prime Minister should – on how much time would this land of Aryabhata and Bhaskara take to count the currency, which has come back. Today, it is exactly three months after that disastrous decision, which you are celebrating, but which India is not. You feel that that was the best thing to be done. पीएम ने यह बात कही थी और आपने कही थी counterfeit currency के बारे में इसी सदन में, इसी संसद में अगस्त महीने में कि counterfeit currency 0.02 प्रतिशत है, चार सौ करोड़। चार सौ करोड़ के लिए 15 लाख करोड़ रद्द कर दिया। कैसा कागज का टुकड़ा कहा? बहुत अच्छी बात कही। मुझे एक बात पूछनी है कि कितना पैसा उस 15 लाख करोड़ में से counterfeit था, कितना पैसा उसमें से terrorist के पास था? हकीकत यह है कि आपने पांच सौ रूपया और हजार का नोट काटा, वह भी ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और दो हजार का नोट ले आए, जिसका टूटा नहीं मिलता। पांच सौ का नोट, सौ का नोट, पचास का नोट, बीस का नोट वह है नहीं, छापा नहीं। वित्त मंत्री जी, मुझे अफसोस है, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और इनके प्रति शुभकामनाएं भी रखता हूं कि आपने कल इस सदन के अंदर यह कहा कि एक भी दिन के लिए कोई कैश की शॉर्टज नहीं थी। तो हिन्दुस्तान के औसतन जो 11 करोड़ आदमी रोज खड़े होते थे एटीएम और बैंक के बाहर गुहार लगाते थे, भीख मांगते

[श्री आनन्द शर्मा]

थे कि हमारा पैसा हम को दे दो, जो उनको नहीं मिला। यह उनको पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, तो क्या वह शॉर्टज नहीं थी? शायद उन लोगों के पास शॉर्टज नहीं थी जिनके पास bank vault से पिछले दरवाजे से सीधा पैसा जाता था। क्यों लोगों के पास दसियों करोड़ रूपया मिला? कैसे गया वह पैसा? आप कहते हैं कि आपकी सरकार के समय कुछ गलत नहीं हुआ, मैं इसको ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to conclude it now.

SHRI ANAND SHARMA: I have some important issues to raise, Sir. Please. This is the only time when we get heard, Sir. Please. I respect you, Sir, and I urge you. I will conclude it. इनसे मुझे पूछना है कि terror funding की बात तो छोड़ दीजिए, terrorists के पास दो हज़ार के नए नोट मिले – करोड़ों में मिले, बांदीपुरा में मिले, और जगह पर भी मिले। पिछले सप्ताह बंगलादेश में 2,000 रूपए के नोटों की एक बड़ी चेस्ट पकड़ी गयी, जो counterfeit हैं। तो आपने counterfeit रोक लिया – बंगलादेश में छप गए, terrorists के पास पहुंच गए। Counterfeit Currency दुनिया के सभी देशों में हो जाती है। अमेरिका का जो डॉलर है, सबसे ज्यादा उसकी नकल बन जाती है। क्या उन्होंने उसे खत्म कर दिया, रद्द कर दिया? उन्होंने यह कहा कि मैं बहुत सोच-समझकर फैसला करता हूं, बड़ी तैयारी के साथ करता हूं। आपको बधाई हो, Operation Secrecy की।

दूसरा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, पर हिन्दुस्तान के गरीब पर, किसान पर, मज़दूर पर, गृहिणियों पर, हमारी बहू-बेटियों पर, जिनमें हज़ारों-लाखों की शादियां टूट गयीं, कई बेटियों ने खुदकुशी कर ली – यह सर्जिकल स्ट्राइक आपने उन पर की। आपने उनको तकलीफ पहुंचाई है और आप कहते हैं कि आपने काले धन वालों पर पेच कस दिया! एटीएम और बैंकों के बाहर जो लाइनों में खड़े थे, कतारों में खड़े थे, उनमें से कौन साहूकार था, कौन पूंजीपति था, कौन काले धन वाला था? आपने उन सारे गरीब लोगों को, जो तकलीफ में खड़े थे, एक साथ कलंकित कर दिया कि सारे लोग बेईमान हैं, इनके पास काला धन है, मैंने इनको लाइन में लगा दिया है। ऐसा कहना अच्छा नहीं है। हम तो आपसे कहते हैं, हम आपके सामने उन लोगों की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, जो स्वयं अपनी बात नहीं कह पाते, जो मज़बूर हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो कहते हैं कि जो भी आलोचना करे — क्योंकि आपमें सहनशीलता नहीं है, आपको किसी की बात नहीं सुननी — वह देश विरोधी बात कर रहा है। जो आपको प्रश्न करता है, उसको कहते हैं कि वह काले धन का समर्थक है। कृपा करें और इस भाषा को बदलें। जैसा मैंने कहा, केवल आप ही वह नहीं हैं, जो देश के हित को समझते हैं — देश के हित को सब लोग जानते हैं। वित्त मंत्री जी, मुझे आपसे एक चीज़ कहनी है कि अगर आपने सब सोच-समझकर तैयारी के साथ किया था तो आज भी वह पैसा पूरा नहीं छपा। आपको पता होता तो जरूर पहले आप नोट छाप लेते। अब यह पता लग गया कि क्या होगा, कैसे यह भरपाई होगी। अच्छा है कि इस देश में बड़ा सब्र है, भारत के लोग स्वीकार कर लेते हैं और तकलीफ को भी बरदाश्त करते हैं। अगर आप कह देते कि इसमें कहीं कोताही रह गयी, गलती हो गयी तो इसमें आपको कोई सज़ा नहीं देता। हमने नहीं कहा कि प्रधान मंत्री को सज़ा मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र में जनता सज़ा दे देती है, वह सज़ा जरूर मिलेगी, लेकिन आपने कहा

कि पचास दिन के बाद सब चीज़ ठीक हो जाएगी, वरना मुझे जो सज़ा देनी हो, किसी चौराहे पर खड़ा करके, वह सज़ा आप दे दीजिए। वह कौन सा चौराहा और कौन सी सज़ा है, आप खुद ही तय कर लें। आप तो हुक्मरान की तरह फैसले करते हैं, अब अपनी सज़ा भी शायद खुद ही तय करेंगे। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। जो बैंक में खातों में पैसा है, वह लोगों का है, उनकी मेहनत का पैसा है, मज़दूरी का पैसा है, वह बेईमानी का पैसा नहीं है। कौन से कानून ने आपको अधिकार दिया कि आज तक आपने उस पर राशन लगाया हुआ है, आज तक पाबंदी लगायी हुई है? किसी के घर में बेटी की शादी हो, तो प्रधान मंत्री और आप तय करेंगे कि कितना पैसा वे निकालेंगे? आप तय करेंगे कि दो लाख निकालिए, ढाई लाख निकालिए, उसमें इतने फॉर्म्स और इतने affidavit बना दिए कि किसी को पैसा नहीं मिला। ...(**समय की घंटी**)... Sir, I will take a few minutes more. I am the only speaker. PM has to reply. This is not fair. I request you to allow me some time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kindly conclude.

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir. I will continue, Sir. Let the Prime Minister come.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In any case, before 5.00 p.m., you have to conclude.

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir; this can't be. I know, let the Prime Minister come.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It was already announced earlier.

SHRI ANAND SHARMA: Let the Prime Minister come. What is the rule, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I had announced it earlier.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I request you to allow me. I have a few things to say. ...(*Interruptions*)... सर, मुझे वित्त मंत्री जी से यही पूछना है कि अगर आपने सब चीज़ सोचकर की थी, तो हुआ क्या?

उपसभापति महोदय, 8 नवम्बर के बाद आर.बी.आई. के 121 नोटिफिकेशन्स और सर्कुलर्स जारी हुए। There were a total of 121 notifications and circulars of the RBI. In addition to that, the Finance Ministry notifications and circulars were 23—144 in all! Everybody had been confused as to which new circular would come and which new notification would come next. I had mentioned, Sir, that a joke was going around for weeks. Somebody was asking from the toilet, "Please find out if there is a new notification or circular of RBI." Because, people did not know. In one day, you had come out with two-three circulars. फिर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, पूरी तैयारी थी और लोग खुश हैं। सब लोग खुश हैं, मैं इस पर कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि देश में कोई नुकसान नहीं हुआ है, फायदा हुआ है, लांग टर्म बेनिफिट होगा। लांग टर्म बेनिफिट ठीक है, यह पता नहीं कब होगा? अभी जीडीपी टूटी है, लेकिन वित्त मंत्री जी कहते हैं कि नहीं।

[श्री आनन्द शर्मा]

दुनिया कहती है कि जीडीपी टूट रही है, रोजगार टूट गया। प्रधान मंत्री के गुजरात में मोरबी शहर है, जो ceramic capital है, वहां से चार लाख वर्कर्स वापस चले गए, खेत मजदूर वापस चले गए। वहां से खेत मजदूर वापस चले गए, तभी तो "मनरेगा" की मांग बढ़ी है, क्योंकि खेत मजदूर वापस चले गए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have only four more minutes.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I will take five more minutes. Everything is going on well, Sir. Please allow me. I have lost five minutes and I will add those five minutes. Please allow me. सर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह से रोजगार टूटा है, किस तरह से लोगों की आमदनी टूटी है, मांग टूटी है, बाजार टूटे हैं और सबसे बड़ी बात जो मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, मैं सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार इकबाल पर चलती है, ज़बान पर चलती है। पहले तो भारत के बैंकों की प्रतिष्ठा थी, आज हिन्दुस्तान के लोगों का हमारे बैंकों से विश्वास टूट चुका है। आज आर.बी.आई. की साख टूट चुकी है, क्योंकि आपने उसको गवर्नमेंट के एक महकमे की तरह से ट्रीट किया है। आप 7 नवम्बर को फरमान भेजते हैं कि 8 नवम्बर को बोर्ड की मीटिंग बुलाओ और यह तय कर लो। मेरा यह सवाल है कि प्रधान मंत्री ने यह स्वयं कहा था या नहीं कहा था, यह प्रश्न भी है। मैं बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि 30 दिसम्बर के बाद जिसके पास पुराना नोट हो, वह रिजर्व बैंक के काउंटर पर जाकर बदल ले। 2 जनवरी का दिन था, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के अंदर बूढ़े थे, महिलाएं थीं, गांव के लोग थे और एक हमारी भारत की जवान बेटी, एक साल के बच्चे को बाजू में लेकर खड़ी थी ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You spoke for thirty-eight minutes.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, this is not fair. Every time you ring the bell, Sir. The Prime Minister is not here and you want me to sit down! We are having a debate, Sir. This is not proper, Sir. ...(*Interruptions*)... I know, the Prime Minister is not used to listening to anybody.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; the Prime Minister has to speak at 5.00 p.m. I am only cautioning you of the time. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Deputy Chairman, Sir, with due respect, your bell came when I was narrating a heart-rending incident. When I was narrating a tragedy, the bell came. When this young lady standing in a queue, with her one year-old child in her arm, with ₹ 4,000 in old notes, she was pushed around. The old people were beaten up in front of the RBI. They were pushed around and many got injured. This lady fell down. The child too fell down. All the TV channels showed it. हमारी वह बेटी दुख में, तकलीफ में निर्वत्र हो गई, देश की राजधानी में, रिजर्व बैंक के सामने। एक आपको वेदना नहीं है। आपने उसकी निन्दा नहीं की। आपने उसकी जांच नहीं

5.00 P.M.

करायी। प्रधान मत्री की ज़बान पर लोग पैसा लेकर रिजर्व बैंक के काउंटर पर आए थे। अगर देश के प्रधान मत्री का इकबाल खत्म हो जाता है, तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, सरकार में नहीं, राजनेताओं में। उन्होंने आपकी बात मानी थी, तकलीफ सही थी, लेकिन आपने उनके साथ ये बदसलूकी की। इस देश के अंदर कई मिसालें हैं। उपसभापति महोदय, सच्चाई कड़वी होती है, आप लोग सुनना नहीं चाहते। अच्छा होता कि आपके माननीय प्रधान मंत्री दूसरों की बात भी सुनते, आपकी भी बात सुनते। उपसभापति जी, चाहे वे देश की नीतियां हैं, चाहे वे विदेश की नीतियां हैं, पर हालात क्या हैं?

श्री उपसभापतिः आनन्द शर्मा जी, जरा सुनिए। आपने 40 मिनट ले लिए हैं।

श्री आनन्द शर्माः अभी और लूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How much time your party has taken, tell me. Now you conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Just forget it, Sir. This is an important issue. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now you conclude. ...(*Interruptions*)..

SHRI ANAND SHARMA: You said that I am the last speaker. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you are the last speaker. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: This is unfair, Sir. ...(*Interruptions*)... यह क्या हो रहा है? आप देखिए

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have been informed that after your speech is over, the Finance Minister would like to say a few words and after that the Prime Minister will come. ...(*Interruptions*)... Therefore, you have to stop. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः उपसभापति जी, आनन्द शर्मा जी ने लगभग एक घंटे से ज्यादा बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छी बात कही।

SHRI ANAND SHARMA: Let the sense of the House be taken. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः मुझे लगता है कि आनन्द शर्मा जी की सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: I will speak for seven minutes more. ...(*Interruptions*)... Please. I would have finished if I had not been stopped all the time. ...(*Interruptions*).. No, Sir. I will speak. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: His party has taken so much time. ...(*Interruptions*)... Later on you will complain against it. ...(*Interruptions*)... You will say that I gave them more time. ...(*Interruptions*)... How can it be? ...(*Interruptions*)... After your speech, the Finance Minister wants to intervene and then only the Prime Minister will come. That is what I am saying. ...(*Interruptions*)... I said what I have been told. ...(*Interruptions*)... I said what I have been informed. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: I am not blaming the Chair. ...(*Interruptions*)... We understand because we have also been in politics for long. We know what is happening. ...(*Interruptions*)... We know what is happening since yesterday. We are not children. But that is fine. ...(*Interruptions*)... I have one thing to say. अब यह नयी बात हुई क्योंकि पैसा छपा नहीं, तैयारी हुई नहीं, जुबान टूट गयी, इकबाल टूट गया, अब करोड़ों रूपया "कैश लेस" करने पर खर्च हो रहा है। अच्छा, दुनिया में कौनसा देश "कैश लेस" है? भारत में तो 90 परसेंट से ज्यादा लेन-देन कैश ट्रांजैक्शंस में होता है। फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम होगा

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now conclude please. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः आपको मालूम होगा वर्ल्ड बैंक की फाइनेंस इंक्लूजन रिपोर्ट, । am referring to the World Bank Financial Inclusion Report which says that less than 7 per cent of Indians use cheque for transactions, less than 2 per cent Indians are using credit cards and debit cards. ...(*Interruptions*)... भारत के अंदर साढ़े छः लाख गांव हैं और 1 लाख 32 हजार बैंक ब्रांचेज़ हैं। उनमें भी 73 परसेंट शहरों के अंदर हैं। देश में 2 लाख 12 हजार एटीएम्स हैं और हिन्दुस्तान के किसी गांव में एटीएम नहीं है। आपने कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण बैंक्स को पैसा नहीं दिया, न नोट बदलवाने की अनुमति दी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: You give me seven minutes more. ...(*Interruptions*)... After every thirty seconds if you ask me to sit down, I am not going to sit down. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken much more time than allotted to your party. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: You are not allowing me to speak. ...(*Interruptions*)... You are not allowing me. ...(*Interruptions*)... These are important issues which I am raising. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If each party starts behaving like this, what do I do? ...(*Interruptions*)... देखो, यह गलत होगा।

SHRI ANAND SHARMA: After every ten seconds, you are interrupting me. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now conclude, please. ...(*Interruptions*)... आनन्द शर्मा जी, आपने बहुत बोला है।

SHRI ANAND SHARMA: It is in the interest of the functioning of this House that I am given those few minutes. I am requesting and allow me to conclude. सर, मुझे एक चीज कहनी है, कि जिस हिन्दुस्तान में as per the RBI, 43 per cent of Indians have no bank accounts, that is 55 crores, even if I accept your number on *Jan Dhan* accounts, yet a large number of them are not operational. There are no transactions. If over 80 crore Indians have no bank accounts, who will give them a credit card or a debit card? सर, आज सरकार और प्रधान मंत्री Paytm को प्रमोट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, आप प्रमोट जरूर करें, आप 'भीम' को भी प्रमोट करो । ...(**व्यवधान**)... ...(*Interruptions*)... Sir, after every ten seconds if they interrupt, how can I conclude? They don't even give me 30 seconds uninterrupted. Sir, this is not fair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Why is the Prime Minister not here? There should be some respect for the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Let them say, "He will not come." He is not coming, we know that. He is afraid. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, इनका भाषण हो गया है। ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... प्रधान मत्री जी intervene करेंगे, चिन्ता मत करिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... Now listen to me. I have already said... ...(*Interruptions*)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... You please sit down. ....(*Interruptions*)...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): If the Prime Minister is correct, why should he not be here?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Reddyji, please sit down. Be reasonable. ...(*Interruptions*)... Listen to me also. Please be reasonable. ...(*Interruptions*)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... How much time can your party be given? You have taken much more than what is due. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. CHIDAMBARAM (Maharashtra): That is not relevant now. ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: You said he will be the last speaker. After that the Prime Minister will speak. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... Shri Sanjiv Kumar, please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot allow if a Member wants to indefinitely speak. This cannot be allowed. I cannot allow that because I am told that the Leader of the House also wants to intervene. It is already 5.10 p.m. A lot of time has been given. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have a point of order.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You said the Prime Minister will come. Why is he not here?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anand Sharmaji's party time was fully exhausted yesterday. Even then I allowed. What is the rationale? We cannot function in this way.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, have you changed the rules of the Rajya Sabha?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are changing. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, why is the last speaker, Shri Anand Sharma, not being allowed to speak? The Prime Minister has to reply to the queries raised by us. Where is he? My question is, is there a rule that a debate will only start when he speaks? Sir, what is this? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have a point of order. Now, let me reply to you. ...(*Interruptions*)... Yes, it is a valid point of order. Allow me to reply to that.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, have you fixed the time? Has the Prime Minister got time to speak? This is not fair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You raised a point of order. You are not allowing me to speak. Now, listen to me. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: He should be here to respond to our queries. Have you changed the rule that the Prime Minister will only come...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Digvijayaji, listen to me.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Will he not listen to us?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, why is the Prime Minister not here?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Show me the rules book, Sir. Can the Prime Minister tell us at what time he will respond?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen to me. Are you ready to listen to me? बैठिए, आप लोग बैठिए। Let us not quarrel now. Each party has time allocated... ...(*Interruptions*)... Let me speak. ...(*Interruptions*)... Let me complete. ....(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Can the hon. Prime Minister dictate the House? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me complete. ...(*Interruptions*)... You are such a senior Member and not allowing me to speak! ...(*Interruptions*)... Allow me to speak. ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)... आप लोग बैठिए **...(व्यवधान)...** I have no problem. ...(*Interruptions*)... Let me complete. बैठिए, बैठिए **...(व्यवधान)...** बैठिए, बैठिए **...(व्यवधान)...** ...(*Interruptions*)... Please, sit down. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी जी बैठिए। **...(व्यवधान)...** My problem is not that. ...(*Interruptions*)... Listen to me. ...(*Interruptions*)...There should be some kind of a reasonable allocation of time. ...(*Interruptions*)... Now, let me complete. ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)... Are you ready to listen to me? You are a very senior leader. I respect you very much. But, listen to me. ...(*Interruptions*)... Time allocated to all parties exhausted yesterday itself. ...(*Interruptions*)... Let me say. ...(*Interruptions*)... But Shri Anand Sharma was the last speaker and we could not allow him yesterday, because so many names came. So, Shri Anand Sharma's name left out. Therefore, it was decided that Shri Anand Sharma should be allowed to speak and I allowed him. And, it was announced in this House that, in any case, he has to stop at 5.00 p.m., because at 5.00 p.m. the Prime Minister is expected to reply. ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... What is this? ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... What are you doing? Sit down. ...(*Interruptions*)... No, no. You cannot do this way. ...(*Interruptions*)... I am on my legs. ...(*Interruptions*)... But, so many names came in between since yesterday and all of them have been accommodated. Let me say that. ...(*Interruptions*)... Even on the Payment of Wages Bill, so many names came. All of them have been accommodated. Even yesterday, a dozen extra names came, I have accommodated them. ...(*Interruptions*)... So, in between, I was informed that the Leader of the House wants to speak. So, I said, 'Okay. At 5.00 p.m. Shri Anand Sharma should stop and the Leader of the House should speak.' ...(*Interruptions*)... That is natural. ...(*Interruptions*)... What is the harm in that? ...(*Interruptions*)... No, no. You have to stop. ...(*Interruptions*)... After that the Prime Minister will come. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... I have got a request from the Whip of BJP that the Leader of the House and Finance Minister wants to speak. ...(*Interruptions*)... That is

[Mr. Deputy Chairman]
why I am stopping him. ...(*Interruptions*)... Otherwise, I would not have stopped him and waited for the Prime Minister to come. ...(*Interruptions*)... That is my problem. ...(*Interruptions*)...You understand. ...(*Interruptions*)... What do I do? ...(*Interruptions*)... What do I do? ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, let me suggest a solution to this. ...(*Interruptions*)... Let me suggest that as soon as the hon. Prime Minister walks in, Mr. Anand Sharma will sit down. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Suppose, if the Prime Minister decides not to come, Mr. Anand Sharma will not stop. What is this? ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Ah! That is the game. ...(*Interruptions*)... You exposed the fact. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः 5 बजे के बाद प्रधान मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। आनन्द जी को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... ऐसा कहना, आपकी महानता है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Parliament cannot function like this. ...(*Interruptions*)... Rajya Sabha cannot function like that. ...(*Interruptions*)... The Chair has to control. ...(*Interruptions*)... The Chair has to allot time. ...(*Interruptions*)... I have allotted time. I have given him forty-four minutes, up to 5.00 p.m. Now, he has to stop.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I only wanted to get this information from you that hon. Prime Minister is not coming. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I did not say that. ...(*Interruptions*)... I did not say that. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... I did not say that. ...(*Interruptions*)... But, we cannot function like that. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आप चिन्ता मत कीजिए, प्रधान मंत्री जी जरूर आएंगे। ...(**व्यवधान**)... माननीय आनन्द शर्मा जी का दो घंटे का भाषण हम सबने सुना है, ...(**व्यवधान**)... इसलिए आप आनन्द शर्मा जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि उनकी सारी बातें आ चुकी हैं और उनको दोहराने से अब कोई फायदा नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We cannot function like that. ...(*Interruptions*)... We cannot function like that. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I want a ruling from you. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is not the issue. ...(*Interruptions*)... The issue is that he has spoken for forty-five minutes. ...(*Interruptions*)... It is much more than any party's time. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I want a ruling from you. ...(*Interruptions*)... Can the hon. Prime Minister dictate the House at what time he will speak? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. He cannot. ...(*Interruptions*)... Nobody can. ...(*Interruptions*)... It is up to him. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the way the ruling party is behaving is as if the hon. Prime Minister dictates rule in this House. ...(*Interruptions*)...We are objecting to that. ...(*Interruptions*)... Can he dictate the House? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But, who is violating the rule now? The Chair has given him 45 minutes. Now, when the Chair is asking him to conclude, he is not concluding. Who is violating? ...(*Interruptions*).... So, what should I do? Okay, you want three more minutes. You can take three more minutes. Agreed.

श्री आनन्द शर्माः सर, बात ऐसी है कि हम ऐसी अस्वस्थ परंपराएं बना रहे हैं, अस्वस्थ मानसिकता का तो मैंने जिक्र कर दिया। अब कोई अच्छा भी काम करे, कोई अच्छा भी बोल रहा हो, परन्तु बीच-बीच में दस-दस सेकंड के बाद आपकी टोका-टोकी जो चलती है, उससे तो कोई भी नहीं बोल पाएगा, जैसे आप भी नहीं बोल पाए। प्रधान मंत्री जी अच्छा बोलते हैं, अगर दस-पंद्रह सेकेंड के बाद उनको टोका-टोकी होगी, तो अच्छे से अच्छा वक्तव्य खराब हो जाएगा। आप इसे बंद करिए। हम भी पुराने सदस्य हैं, I am a senior Member of this House. I first came to this House in 1984. Please give me that respect. मुझे आपसे यह बात कहनी है। दूसरे कई विषय है, मैं उन पर नहीं बोलूंगा। विदेश नीति की मेरे साथियों ने चर्चा की। आज जो बदहाली है, the kind of policy, which you are pursuing, is alienating even the time-tested friends of India, particularly in our neighbourhood. What is happening? The Prime Minister does not believe in a debate. After all, in our democracy, we have always believed in discussions. We can differ. But we can also share our experiences. Former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, is here. He can also give his own inputs. But the Prime Minister thinks that he knows everything and there is no need to consult. I have one issue to raise, which should concern this House. ...(*Interruptions*)...

श्री रवि शंकर प्रसादः आपके ही लोग आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः देखिए, बात ऐसी है कि सर, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और पीठ की इज़्ज़त करता हूँ। I want to put you a question. Since the hon. Chairman and you announced in the House yesterday, you also announced today that Anand Sharma is the last speaker and after that the Prime Minister will reply. Where is the Prime Minister? Where is he? ...(*Interruptions*)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In between, I was informed that the Finance Minister will also speak. So, I have to accept that. ...(*Interruptions*)....

श्री आनन्द शर्माः सर, एक चीज मैं बोलूं, इसको गौर से सदन सुने, पूरा सदन इस बात को सुने। आपने कहा "सबका साथ, सबका विकास" और भाषण में कहा "चर्चा", "संवाद", लेकिन संवाद एक तरफ का नहीं होता कि वे बोलें और हम सुनें। संवाद दो तरफ से होता है, संवाद व्यक्ति अपने आप से नहीं कर सकता है। तो यह कैसे संभव है? मुझे एक चीज कहनी है, जो एक गंभीर बात है। प्रधान मंत्री जी ने अभी हाल में अमरीका के राष्ट्रपति से बात की, जो उनका अधिकार है, आप देश के प्रधान मंत्री हैं, लेकिन हम अब तक सवाल कर रहे हैं कि एच1बी1 वीज़ा का, जो वहां पर पांच लाख हिन्दुस्तानी वहां हैं, उनके बारे में has he sought any credible assurance about that? जो हमारे आईटी के लोग हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ यह कहना कि बहुत अच्छी बात हो गई। यह तो वक्त बताएगा कि कैसी बातचीत हुई। आपने उसके बारे में क्या क्रेडिबल एश्योरेन्स ली? मैं पूछना चाहता हूँ।

सर, मुझे एक चीज और कहनी है कि गलतियां होती हैं। ...(**व्यवधान**)... गलतियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको स्वीकार करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि हम लोगों से कोई गलती न हो, परन्तु सरकार अपनी गलती न माने, प्रधान मंत्री अपनी गलती न माने और हमारे मित्र तो कहें कि एक दिन भी कैश की शॉर्टेज न हो, तो बड़े दुख की बात हो जाती है। सर, मुझे एक चीज कहनी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude.

श्री आनन्द शर्माः सर, मैं conclude कर दूंगा, परन्तु मेरी बात तो सुन लें। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the sense of the House may be taken. ...(*Interruptions*)... I think, I should continue. ...(*Interruptions*)... Take the sense of the House. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. No sense of the House is required on this. ...(*Interruptions*)... Before the Prime Minister, the Finance Minister has to speak. I have already announced this. ...(*Interruptions*)... Before the Prime Minister, the Finance Minister has to speak. I don't know how long he will take. ...(*Interruptions*)... So, Anand Sharma*ji*, now sit down. ...(*Interruptions*)... आनन्द शर्मा जी, अब आप बैठिए।

श्री आनन्द शर्माः सर, मैं अभी नहीं बैठूँगा, मैं अपनी बात खत्म करूँगा।

श्री उपसभापतिः आप मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं?

श्री आनन्द शर्माः सर, मैं अभी खत्म करूँगा। I will conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are putting me into so much of difficulty. ..(*Interruptions*)..

श्री आनन्द शर्माः सर, मुझे अपनी बात खत्म करने दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री आनन्द शर्माः सर, मुझे एक चीज कहनी है कि मैंने जो गलतियों का ज़िक्र किया, बार-बार ये गलतियां न होतीं, अगर हमसे नहीं, तो वे अपने वरिष्ठ साथियों के साथ सलाह-मशविरे से फैसले करते। पर सलाह-मशविरा किनसे करें? सलाह-मशविरा उनसे तो नहीं कर सकते, जो टोक नहीं सकते, जो चेता नहीं सकते कि इस फैसले से ऐसा हो सकता है, इस नीति से यह गलत हो सकता है। एक भय का वातावरण है। जब पूरा विपक्ष डरता है, तो मैं भी जानता हूँ कि काफी लोग भयभीत रहते हैं। जो नहीं हैं, बोलना मत कि हम डरते नहीं हैं, नुकसान हो जाएगा। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री आनन्द शर्माः मैं खत्म कर रहा हूँ। सर, फिर से घंटी। मुझे यह कहना है कि जो लोग इनको समझा सकते थे, जो लोग इनको टोक सकते थे, वे बड़े नेता थे, अगर उनसे सलाह-मशविरा करते, तो गलतियां न होतीं, लेकिन उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। मुझे प्रधान मंत्री को एक सलाह देनी है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL: If he doesn't want to listen to us, why should we listen to him?

SHRI ANAND SHARMA: Correct.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right, please conclude.

श्री आनन्द शर्माः मैं खत्म करता हूँ, आप उनको हमारी तरफ से कह देना,

"बात मन की सिर्फ कहते, सुन भी तो लेते कभी,
क्या-क्या है मन में देश के, प्रधान मत्री समझ भी लेते कभी।"

न वो सुनने आए, न समझने आए। हम भी मजबूर हैं। अगर यह अहंकार है, तो विनम्रता से सरकार चलती है, अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि आप हमेशा यहां रहेंगे, ...(**समय की घंटी**)... तो वह बुलेट ट्रेन जल्दी बना दो, उसी बुलेट ट्रेन में 2019 में प्रधान मंत्री और आप सबको हम रवाना करेंगे। हरी झंडी हम दिखाएँगे और जाएँगे आप। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please sit down. Mr. Jaitley, would you like to say something? ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Don't allow.. ...(*Interruptions*)... Only the Prime Minister should speak, Sir. ...(*Interruptions*)... Only the Prime Minister should speak. No other Minister will speak. Only the Prime Minister will speak. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखरः सर, यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रधान मत्री यहां आएँगे कि नहीं? आप खड़े होकर बोलिए।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ।

श्री उपसभापतिः प्रधान मंत्री आएँगे। The PM will come. He has already said that. ...(*Interruptions*).. The PM will be coming. It is already announced. ....(*Interruptions*).. प्रधान मंत्री आएँगे, आप बैठिए। Please sit down.

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)ः माननीय उपसभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर तीन दिन से चर्चा चल रही है **...(व्यवधान)...** और लगभग 40 सम्मानित सदस्य इस बहस में बोले हैं। प्रधान मंत्री जी थोड़ी देर में यहां होंगे, उस बहस में intervene करने के लिए। मैं आपके समक्ष केवल एक-दो विषय रखना चाहूँगा। आज़ाद साहब ने बहस शुरू की थी, जम्मू-कश्मीर से लेकर demonetization तक और आनन्द शर्मा जी कुछ ज्यादा ही नाराज हैं।

श्री आनन्द शर्माः मैं नाराज नहीं हूँ।

श्री अरूण जेटलीः उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की नए शासन की जो वीज़ा पॉलिसी है, उसका दोष भी हमारे ऊपर डाल दिया। उनकी नाराजगी इस सीमा तक है।

श्री आनन्द शर्माः मैंने यह कहा कि उनसे कोई आश्वासन लिया या नहीं। Credible assurance, that is all what I said.

श्री अरूण जेटलीः लेकिन demonetization के सम्बन्ध में पिछले आधे-पौने घंटे से उन्होंने अपने जो विचार रखे, उसमें खेद इस बात का है कि cash currency के गुण क्या हैं, लगभग उस दिशा में वे भटकते हुए नजर आए। इस देश में सब कुछ कैश के माध्यम से होता है, इस देश में digitization होना बड़ा कठिन है, इस देश में banks की branches नहीं हैं, इसलिए जो यथास्थिति है, वही देश के अंदर चलती रहे, अब कम से कम सन् 2017 में यह तर्क नहीं चल सकता है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Please listen. Please listen. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please don't do that. ..(*Interruptions*)... Please. आप सुनिए **...(व्यवधान)...**

श्री अरूण जेटलीः मैं केवल इतना तथ्य आपके सामने रख दूं कि जब यह सरकार आई थी, तो एक पहला बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया था। हालांकि पुरानी सरकार ने भी उस काम को करने का प्रयास किया था, लेकिन हमने उसको बहुत बड़े पैमाने पर किया। देश में जो financial inclusion का कार्यक्रम था, उसको और तेजी से गति देने की कोशिश की गई। जन-धन एकाउंट्स लगभग उस जनसंख्या के थे, जो आज तक बैंकों तक पहुंची भी नहीं थी। उसको धीरे-धीरे बढ़ाया गया और पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई, आज उन एकाउंट्स की संख्या 27 करोड़ तक पहुंच चुकी है। याद रहे कि इस देश में केवल 25 करोड़ परिवार हैं। पहले एक सीमित जनसंख्या तक ही बैंक एकाउंट्स सीमित थे, इसलिए कुछ लोग उससे वंचित थे। गरीब से गरीब व्यक्ति और ज़ीरो एकाउंट वालों को भी यह सुविधा दी गई कि वे उस एकाउंट तक पहुंच पाएं और उस एकाउंट को ऑपरेट करने का उनका स्वभाव बने। सरकार की जो अन्य योजनाएं थीं, उनका गरीब लोगों को फायदा मिल सके, इसके लिए जन-धन एकाउंट्स के तहत, 'आधार' के साथ उनका पूरा डेटा बैंक बनाया गया। आज कितने ही सरकारी कार्यक्रम ऐसे हैं, जिनके माध्यम से गरीब लोगों को सरकारी सहायता मिलती है, तो वह सहायता सीधे उन खातों में जाने लग गई है। वे खाते, जिनमें से लगभग 78 फीसदी ज़ीरो एकाउंट के थे, आज उनमें से अधिकतर खाते

एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं।

दूसरा, काले धन के खिलाफ सरकार ने अचानक कदम उठा लिया हो, ऐसा नहीं था। पहले दिन से, जब से यह सरकार बनी थी, हमारा चुनावी मुद्दा भी यही था। 26 मई, 2014 को सरकार ने शपथ ली और 29 मई, 2014 को पहला निर्णय यह लिया कि 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, उसके अनुकूल हम लोगों ने SIT का गठन कर दिया। SIT का गठन करने के बाद सरकार ने एक से एक कदम उठाए। एक तरफ जन-धन एकाउंट्स थे, तो दूसरी तरफ सरकार की नीति यह थी कि हम लोगों को विदेशों से अधिक से अधिक सहायता मिल सके। इसके लिए अमरीका के साथ FATCA का समझौता हुआ और स्विट्ज़रलैंड के साथ भी समझौता हुआ। जी-20 में प्रधान मंत्री ने इनिशिएटिव लिया कि जिन लोगों ने विदेशों के अंदर अपने assets या खाते रखे हुए हैं, उनके संबंध में एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से विदेश में खर्चा करता है या कोई asset रखता है, तो उसकी जानकारी हिन्दुस्तान को भी मिल जाएगी। जो मामले HSBC के माध्यम से या Liechtenstein के माध्यम से सरकार के सामने आए, उनमें से एक-एक की इन्वेस्टिगेशन सरकार ने समाप्त की, assessment orders किए और जहां-जहां संभव था, उन लोगों के खिलाफ criminal cases register किए गए। सरकार ने आरम्भ में एक बहुत अच्छा कानून बनाया, जिसका सभी वर्गों ने समर्थन किया। उस कानून के अनुसार जिन लोगों के विदशों में साधन थे या कोई एकाउंट्स थे, उनको डिक्लेयर करने के लिए उन लोगों को एक higher rate of taxation पर मौका दिया गया। उसमें सरकार ने दस साल तक की सजा का प्रावधान भी किया।

1996 से लेकर अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे, जिनको हम Double Taxation Avoidance Treaty कहते हैं, कुछ देशों के साथ वे इस प्रकार के थे कि भारत में उनके ऊपर capital gains tax नहीं लगता था और जिस देश के साथ यह समझौता था, वहां यह टैक्स था ही नहीं, जैसे मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर। इस देश के अंदर यह विषय बार-बार सार्वजनिक चर्चा में आता था कि घूम कर भारत का पैसा बाहर जाता था और round-tripping होकर, उसी रास्ते से वापस आ जाता था। उस पैसे पर न तो इस देश के अंदर टैक्स लगता था और उस देश के अंदर तो टैक्स था ही नहीं। उन सभी समझौतों पर देश में पुनर्विचार किया जाए, यह विषय 1996 से, पिछले 20 साल से चल रहा था। महोदय, वर्ष 2016 एक ऐसा वर्ष था, जिसमें मॉरीशस और उसके बाद साइप्रस और उसके बाद, अभी दिसम्बर, 2016 में हमने सिंगापुर के मामले का रीविजिट किया और जो उसके प्रावधान थे, धीरे-धीरे एक तरह से उनका पुनर्लेखन किया है।

महोदय, देश के अंदर जो काला धन था, उसके लिए बहुत सफल आईडीएस स्कीम सरकार ने घोषित की, जिसमें लोगों ने अपने डिस्क्लोज़र्स किए। उसके बाद, जो बेनामी कानून था, जो वर्ष 1988 में बना था और इनइफेक्टिव कानून था। कानून मंत्रालय की यह राय चली आ रही थी कि यह कानून ऐसा है, इसके तहत नियम या रूल्स बन नहीं सकते और इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। It cannot be made operative. इस प्रकार वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2016 तक संसद का कानून बना हुआ था, लेकिन वह इनऑपरेटिव था। वर्ष 2014-15 में इसका एक संशोधन संसद में पारित कराया गया और वर्ष 2016 से हमने उसे ऑपरेटिव कराया। अगर इन सभी कार्रवाइयों को एक कड़ी के अंदर देखा जाए, तो यह वह सरकार है, जो पहले दिन से, इस देश के अंदर जो काला धन, एक परम्परा और जीवन शैली का एक अंग बन चुका था, उसे समाप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

श्री सीताराम येचुरीः सर, यदि अनुमति हो, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

सर, माननीय वित्त मत्री जी Double Taxation Avoidance Treaty के बारे में बिलकुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन पहले जब बीजेपी की सरकार थी, यह उस समय लागू हुआ था। उस समय हमारी आपत्ति थी कि यही होने वाला है। डबल टैक्सेशन का मतलब है कि दो देशों में वह टैक्स हो और एक ही आदमी या एक ही कॉरपोरेट, दोनों देशों में डबल टैक्स न दे। अब मॉरीशस जैसे देश में capital gains tax है ही नहीं, फिर भी आप उसे यहां भी नहीं देने की अनुमति दे रहे हैं, यह बात है। इसलिए इस बात को भी स्वीकार कर लीजिए कि पहले गलती हो गई, उसे अब सुधार रहे हैं। बीजेपी की सरकार में जो गलती पहले हो गई, उसे अब आप सुधार रहे हैं।

श्री अरूण जेटलीः आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात चैक कर लें, मैं भी चैक कर लूंगा कि मॉरीशस का कोई एग्रीमेंट पिछली एनडीए सरकार के दौरान नहीं हुआ था। वह उससे कहीं पुराना है। It is an old legislation. वर्ष 1996 से उसका रिव्यू चल रहा है। So, it is a legislation that came prior to 1996. इसलिए वह पिछली एनडीए सरकार के समय हुआ, यह ठीक नहीं है। इसलिए इस तथ्य को आप करैक्ट कर लीजिए। बाकी जो तर्क आपने दिया, वह सही था। वह तर्क इसलिए सही था कि Double Taxation Avoidance Treaty का अर्थ यह है कि एक स्थान पर टैक्स दो, भारत में नहीं देना है, तो विदेश में दो। विदेश में वह टैक्स था नहीं और इसलिए यह टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाती थी और इसीलिए इसका एक लालच रहता था और एक टेम्प्टेशन रहती थी कि यहां से घूमकर, राउंड-ट्रिपिंग होकर, यहां का ब्लैक मनी बाहर जाए और फिर घूमकर देश के अंदर वापस आ जाए। मैं केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा था कि आपने यह बात कही, शरद जी से भी मैंने वही बात सुनी कि मॉरीशस के माध्यम से जो ब्लैक मनी का रास्ता बना हुआ है, उसे रीराइट करो। ब्लैक मनी का यह काम देश के अंदर 20 वर्ष से चल रहा था। वर्ष 2016 वह ऐतिहासिक वर्ष था, जिसमें मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर, इन तीनों एग्रीमेंट्स को रीराइट किया गया। इसलिए सरकार ने एक के बाद जो एक कदम उठाया था, वह उस काले धन को रोकने के लिए उठाया।

महोदय, डिमॉनेटाइजेशन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आनन्द जी, आप इस व्यवस्था को समझ लीजिए कि कैश की अधिकतर इकोनॉमी होना, यह किसी देश के लिए बहुत गुणी होने की बात नहीं है।

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

It is no credit to any economy that you predominantly deal in cash because cash has a lot of vices.

SHRI ANAND SHARMA: We should stop printing currency then!

SHRI ARUN JAITLEY: In fact, your own White Paper that you placed in 2012 mentioned that cash is a facilitator of a lot of vices as far as the economy is concerned. So, today, to take a contrarian argument may not be possible for you because cash gives a temptation for a shadow and a parallel economy. Now, it is very easy for you to say that all cash is not black money, but can you deny the

fact... ..(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Can you name one developed country, from America to UK, from France to Germany, that is cashless? Please educate us; we do not know. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: I can name almost every country in the world which is a less-cash economy and which has made an effort to move in the direction of a less-cash economy. I cannot think ...(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Let the speaker continue, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: I cannot think of anyone in the world who now propounds the virtues of dealing only in cash. When you say — बैंक हैं नहीं, digitization संभव नहीं है, कैश में इतना बड़ा ट्रेड होता है, Why are you.. ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः फिर आप नोट छापने बंद कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ARUN JAITLEY: Why are you sprouting virtues of cash when cash can lead to various vices? Your own White Paper of 2012 says that cash is an enabler of a lot of economic vices; it gives you the temptation of dealing in black money; it carries on activities parallel in the economy which evades the economic system; it leads to evasion of taxes; it results in lesser revenues for the Government; it leads to corruption because the instrument of corruption also is cash. All cash is not with the terrorists. But cash is a great enabler of resources as far as terrorism is concerned. It is a hard fact and, therefore, if the Government has taken effective steps to shrink that usage of cash, I don't think that your anger to this extent, which you have said, is really called for. And, therefore, this anger in favour of cash that you have been saying is not called for. Let me just explain it. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादव (बिहार)ः हमारे देश में ऊपर से नीचे तक infrastructure इस तरह का नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं। बाकी आप प्रयास ठीक कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अरूण जेटलीः शरद जी, मैं आपको इतना बता दूं कि जो infrastructure का विषय है, इस देश के अंदर सवा लाख बैंक ब्रांचेज़ हैं, आज तक इतना infrastructure था - 2,10,000 ए.टी. एम. मशीनें बनीं, इस देश में करीब सवा लाख बैंकिंग correspondents थे, जो गांव-गांव जाते थे। वर्ष 2015 में, रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि अब Payment Banks होंगे। उसका असर यह हुआ कि आज जितनी बड़ी Telecom Companies हैं, उनकी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसे वे Payment Banks के अंदर convert कर रही हैं। एक-एक Telecom Company की 5-5 लाख ब्रांचेज़ ये सुविधा देने वाली बन रही हैं। पौने दो लाख पोस्ट ऑफिसेज़ इस देश के अंदर खाली पड़े हुए थे, जिनका कोई प्रयोग नहीं होता था, जो इस infrastructure का हिस्सा बन सकते थे लेकिन नहीं बने। आज उन सबको Payment Banks का लाइसेंस दे दिया गया है। आज technology ने इतनी तरक्की कर ली है कि केवल किसी बैंक की ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच पर जाकर बैंकिंग

[श्री अरूण जेटली]

सुविधा होगी, वह नहीं होगा। जब पिछले सत्र में बहस चल रही थी, सीताराम येचुरी जी को उस समय की मेरी बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि गरीब आदमी क्रेडिट कार्ड का कैसे इस्तेमाल करेगा, मैं आपको बता दूं कि वह आपसे और मुझसे ज्यादा प्रगतिशील है। इस देश में ...(**व्यवधान**)... Let me just complete. ...(**व्यवधान**)...

SHRI T. K. TANGARAJAN (Tamil Nadu): One clarification ...(*Interruptions*)... There is a country where 79 per cent people are digital but it is the most corrupt country in Africa, Kenya ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Rangarajan*ji*, I would have thought where workmen get paid by cash, they are duped. When they are paid by ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. TANGARAJAN: You have changed the Payment of Wages Act. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please stop interrupting. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: We have rightly changed it to say, pay them either by cheque or by the digital mode, so tomorrow they will also be entitled to the social sector schemes which go to their advantage. You should have been in the forefront of having supported this. You are the only Marxist Party, that I know, which sprouts the virtues of cash. ...(*Interruptions*)... What is your objection if workmen are paid by cheque? ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Digital mode is not made available to most of the countrymen. Such a movement is going to cause chaos like it is doing now. Secondly, digital transactions have an extra cost. You are burdening the people with that extra cost. Now, why don't you ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You have had your say. ...(*Interruptions*)... Please, let the speaker continue. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: The question is asked, Sir. That is why I am answering it. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Jaitleyji, please continue.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, let us not underestimate this country. Just as I explained to you that the banking network, even in terms of brick and mortar branches, with the new methodology of payment banks, etc., which is coming up, is going to increase. And, just as the Post Offices have reached every rural area, that is an infrastructure which has now been incorporated into the banking system. Don't underestimate the power of technology because nobody in the world has been

able to defy technology. When you say, "It doesn't reach.", let us forget credit cards because there are only about three crore credit cards. There is an element of credit involved in that. So, there is a cost element. The cost element in other technologies is somewhat lesser. Now, are you conscious of the fact that debit cards in this country alone are about 72 crores, and you are talking in terms of it not reaching anybody! Look at the volumes where it is going. What about the UPI? What about the alternate method of Aadhaar-based technologies which are now being introduced? What about the e-wallets which are being introduced? They are increasing at a great pace. At a great pace, the expansion is taking place and I must tell you that the whole process of what started on 8th of November has catalyzed that process to a great speed.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, one point. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: He has not conceded. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I have one point. He will agree. We read in today's newspaper. ...(*Interruptions*)... Late Sunday evening, the petrol pumps deferred their decision not to accept debit and credit card payments beginning today, that is, January 9. Dealers were protesting the levy of merchant discount rate by banks on debit and credit card transactions.

MR. CHAIRMAN: All right. That is enough. ...(*Interruptions*)... Yechuryji, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: They should understand the reality of our country. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, our misfortune is that not only Yechuryji's ideas but his information is also obsolete, and I tell him what newspaper report he is reading. The newspaper report that he is reading is that on the 9th of January, the petrol pump dealers said that they would not absorb these charges, and, therefore, on the 10th of January, the oil companies said that they would absorb these charges. Therefore, what he is reading is absolutely obsolete. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: All right. ...(*Interruptions*)... Order, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: This issue has already been sorted out. The oil companies are absorbing these charges. It has already been decided. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, this is not a fact. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Don't interrupt. ...(*Interruptions*)... Yechuryji, please, you can't do it. This is not an argument. Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, Sir, yesterday, in an answer to a question in this hon. House, I had said that wherever the Government bodies are involved, they have already decided to absorb those charges. Therefore, this is a methodology, by which you are switching over to various non-cash methods, and, in fact, there are challenges, there are difficulties, but don't find fault with that system and don't start singing virtues of cash because cash has a bit too many vices. That's all I have to say as an intervention.

MR. CHAIRMAN: Now, before the hon. Prime Minister begins, I wish to say that our normal practice is to adjourn at 6 o'clock, but I presume that it is the sense of the House that we will continue.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have a point for clarification.

MR. CHAIRMAN: No; you have had your say.

SHRI ANAND SHARMA: I have a clarification.

MR. CHAIRMAN: What is the clarification? ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः क्योंकि जब हम बोल रहे थे, वे यहां नहीं थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए, उनको सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप पहले उनको सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am asking you. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please listen to the hon. Prime Minister. शर्मा साहब, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, through you, I am asking the hon. Prime Minister that if we have any clarifications, will the hon. Prime Minister respond to them? That is what I am asking.

MR. CHAIRMAN: You cannot anticipate things. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः बाद में वे क्लैरिफिकेशन का उत्तर देंगे या नहीं देंगे? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You can't anticipate what is being said. Hon. Prime Minister.

प्रधान मंत्री (श्री नरेंद्र मोदी): आदरणीय सभापति जी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ।

इस चर्चा में करीब 40 आदरणीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। इसमें श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री ए. नवनीतकृष्णन जी, श्री देरेक जी, श्री डी. राजा, श्री शरद यादव जी, श्री सीताराम जी, श्रीमान अहमद भाई और अभी-अभी श्रीमान आनन्द शर्मा जी ने हिस्सा लिया है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और भी जिन माननीय सदस्यों ने जो विषय रखा है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। जो चर्चा हुई है, वह ज्यादातर demonetization के आसपास रही है। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में यह बुराई आई है, हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जड़ें जमा ली हैं। इससे हम इंकार नहीं कर सकते और इसलिए भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई कोई राजनैतिक लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई किसी राजनैतिक दल को परेशान करने के लिए नहीं है और ऐसा सोचने का कारण भी नहीं है और इसलिए किसी को इस चीज़ को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। इस सदन में हम सब का दायित्व बनता है कि हमें इसके खिलाफ जो भी हम लोगों की संविधान की मर्यादाएं और जो हमारी बुद्धि परमिट करती है, वह करना चाहिए। यह भी सही है कि पैरेलल इकोनॉमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो गरीब का हुआ है। गरीब का हक छीन लिया जाता है और मध्यम वर्ग का शोषण होता है। ऐसा नहीं कि पहले प्रयास नहीं हुए होंगे, पहले भी तो प्रयास हुए होंगे। अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। यह तो आज भी अगर और अधिक प्रयासों की ओर ले जाता है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम कब तक इन समस्याओं को लेकर, कारपेट के नीचे सब चीजें डालकर अपना गुजारा करते रहेंगे?

सभापति जी, एक विषय चर्चा में आता है जाली नोट की चर्चा का। जो आंकड़े प्रचारित हैं, वे आंकड़े वे हैं, जो नोट बैंक तक पहुंचे हैं, उसका हिसाब-किताब है। ज्यादातर जाली नोट कभी बैंक के दरवाजे तक न जाएं, उस व्यवस्था से चलते हैं और आतंकवाद, नक्सलवाद इसको बढ़ावा देने में इसका उपयोग भी होता है। कुछ लोग बड़े उछल-उछल कर कह रहे हैं कि आतंकवादियों के पास से दो हजार के कुछ नोट मिले थे। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में यह जब नोटबंदी के बाद का जो काल खण्ड था, बैंक लूटने का जो प्रयास हुआ और उसमें नए नोट लेकर जाने का प्रयास हुआ, वह जम्मू-कश्मीर में हुआ, क्योंकि जाली नोटों पर स्थिति बनने के बाद रोजमर्रा के कारोबार के लिए उनके सामने दिक्कतें आई थीं। बैंक लूटने के कुछ ही दिनों बाद जो terrorists मारे गए, उसमें वे नोट हाथ लगे। इसका सीधा-सीधा संबंध है, इसको हमें समझना चाहिए और कोई कारण नहीं है कि हम ऐसे लोगों के पक्ष में अपना विचार क्यों रखें? कोई कारण नहीं है। ये लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ हमें एक स्वर से लड़ना ही पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति को ताकत तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि बेइमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। बहुत वर्षों पहले एक वांचू कमेटी बनी थी और नोटबंदी की आर्थिक जरूरतों के संबंध में उस कमेटी ने उस समय, जब श्रीमती इंदिरा गांधी थीं, अपनी रिपोर्ट दी थी। उस समय यशवंतराव चव्हाण जी उससे सहमत भी थे और उसे आगे बढ़ाना चाहे थे, लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि हम तो राजनीति में हैं, चुनाव वगैरह लड़ने होते हैं। ...(**व्यवधान**)... यह गोडबोले जी की किताब में है। ...(**व्यवधान**)... गोडबोले जी की किताब में है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): ये क्या बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः यह गलत है। ...(**व्यवधान**)... यह गलत बात है। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा एक प्रश्न है। ...(**व्यवधान**)... I have a point or order. I will raise it. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदीः गोडबोले जी, जो श्री यशवंतराव चव्हाण के ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना है कि इंदिरा जी अब इस ...(**व्यवधान**)... देश की शहीद प्रधान मंत्री हैं। ...(**व्यवधान**)... मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदीः अच्छा होता कि गोडबोले जी की इस किताब पर ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में ...(**व्यवधान**)... You expunge it because Indiraji and Yashwantrao Chavan ...(*Interruptions*)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... पहले सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेंद्र मोदीः आनन्द जी, मुझे पूरा सुनने के बाद आप खड़े होइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: The Prime Minister cannot refer to one Executive Assistant's book. ...(*Interruptions*)... आप अरूण जेटली जी के साथ जब बैठते हैं तो उनके पीए साथ में होते हैं, बात करने के लिए? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please continue.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडु)ः उन पर कोई आरोप नहीं है।

श्री नरेंद्र मोदीः जब गोडबोले जी की किताब छपी, अच्छा होता, उस समय आपने इतनी जागरूकता दिखायी होती और उस किताब के खिलाफ आवाज़ उठायी होती। आप सो रहे थे क्या? आप उस समय क्या कर रहे थे? इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सो ही रहे हैं? आपकी जगह मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता, लेकिन आपने नहीं किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः आप लगा रहे हैं।

श्री नरेंद्र मोदीः आज जब गोडबोले जी की किताब की चर्चा हो रही है तो आपको ज़रा ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः गुजरात में आपके ऊपर ...(**व्यवधान**)... हजारों लोग ...(**व्यवधान**)... क्या बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश): छोटे-छोटे लोगों को लेकर आप ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Is he speaking on record? ...(*Interruptions*)... He is quoting a book. Is he speaking on the facts of the record? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The speech is on record. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदी: आज उसकी स्थिति थोड़ी और आगे बढ़ी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: If there was a meeting, ...(*Interruptions*)... Is he quoting from the record? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It is not courteous to interrupt like this. Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदी: जब वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, तब काला धन, नकद – वहीं तक समस्याएं सीमित थीं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: अपने केसों का देखिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेंद्र मोदी: आज काला धन, आतंकवादी संगठन, जाली नोट का कारोबार, drugs का कारोबार, हवाला का कारोबार, यह सब जीवन के कई क्षेत्रों तक फैल चुका है, इसलिए इसकी व्यापकता बढ़ी है। जिस समय 8 नवम्बर को निर्णय किया, तब जाली नोट वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कोई छोटा बैंक होगा, जहां साधन नहीं होंगे और वहां अगर ऐसे नोट घुस गए होंगे तो रिजर्व बैंक तलाश करेगा, लेकिन जाली नोट तो उसी समय neutralize हो गए और उसका हिसाब अगर किसी के पास है तो आश्चर्य होता है कि वह हिसाब इनके पास कैसे है? जाली नोट तो उसी समय neutralize हो गए और यह सब कुछ इसी के कारण हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरी: आप क्या बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेंद्र मोदी: आपने एक टीवी खबर भी देखी होगी। ...(**व्यवधान**)... दुश्मन देश में जाली नोट का बहुत बड़ा कारोबार करने वाले को आत्महत्या करनी पड़ी थी। यह न्यूज़ टीवी पर बहुत दिन चली थी। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: ज़ी टीवी पर। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेंद्र मोदी: आप देखिए, हमारे देश में तीस-चालीस दिवस में 700 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया — यह पहली बार हुआ है। नवम्बर-दिसम्बर के दरमियान 40 दिन में करीब 700 लोगों ने सरेंडर किया है और उसके बाद भी यह प्रक्रिया चल रही है। माओवादी सरेंडर करें और उसका संतोष इस सदन में किसी को न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ मतलब और है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरी: क्या सरेंडर्स इस वजह से हो रहे हैं?

श्री नरेंद्र मोदीः अब उसमें तो आप ज्यादा मार्गदर्शन कर सकते हैं।

श्री सीताराम येचुरीः करेंगे, करेंगे, लेकिन बाद में। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेंद्र मोदीः यह भी बात सही है कि देश की formal व्यवस्था में धन होना बहुत जरूरी है। हजार के नोट छपने के बाद सामान्य चलन में जाते ही नहीं थे, पांच सौ के नोट बहुत कम जाते थे, हजार के नोट बहुत कम जाते थे और बंडल के बंडलों का कारोबार चलता रहता था। यह हकीकत है और इस हकीकत से हम इन्कार नहीं कर सकते हैं। अब जब इतनी बड़ी करेंसी बैंकों के पास आई है, तो स्वाभाविक है कि बैंकों की सामान्य व्यक्ति को पैसे देने की ताकत बढ़ेगी। एक साथ सभी बैंकों ने ब्याज दर कम की हो, ऐसा पहली बार हमारे देश में हुआ था। बैंक का लाभ सामान्य लोगों के लिए... यहां पर असंगठित कामगारों की बात हो रही है। सचमुच में, आप लोगों से, खासकर सीताराम येचुरी जी और उनकी पार्टी से तो यह अपेक्षा रहेगी कि असंगठित कामगारों को उनके वेतन के संबंध में सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह हकीकत है कि जितना कहा जाता है, उतना दिया नहीं जाता है। दिया जाता है, तो उसमें भी बाहर एकाध आदमी खड़ा रहता है, वह काट लेता है। इन बीमारियों को हम सब जानते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरीः अब वेतन भी नहीं मिल रहा है।

श्री नरेंद्र मोदीः ऐसी बहुत सी बीमारियों से हम परिचित हैं और इसीलिए अगर यह व्यवस्था हम खड़ी करते हैं, तो उसका श्रमिकों को लाभ मिलेगा, समय रहते ई.पी.एफ. के साथ जुड़ेंगे, ई.एस.आई. स्कीम के साथ भी जुड़ेंगे। श्रमिकों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा इसके कारण सम्भव होने वाली है और इस दिशा में हमारा प्रयास है।

मैं असम के टी बागान का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां की सरकार ने थोड़ा initiative लिया। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने बैंक में करीब 60 लाख खाते खुलवाए। मोबाइल ऐप पर उनको कारोबार करना सिखाया। शुरू में यूनियन वालों ने मना किया, नहीं कैश में पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें जुड़ी हुई थीं। इसके कारण इन चाय बागानों के मजदूरों को पूरा वेतन मिलने लगा और उस इलाके में उनका कारोबार सुरक्षित हुआ। यह एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियेंस है।

इसी प्रकार से नोटबंदी के समय में कोई विदेशी अखबार को क्वोट करते हैं, कोई विदेशी अर्थशास्त्रियों को क्वोट करते हैं। यह एक ऐसा विषय है कि अगर आप 10 क्वोट करेंगे, तो मैं 20 क्वोट कर सकता हूं। अगर आप 10 महापुरूषों को क्वोट कर सकते हैं, तो मैं 20 महापुरूषों को क्वोट कर सकता हूं। यह इसलिए हो रहा है कि विश्व में इसका कोई parallel ही नहीं है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा और इतना व्यापक निर्णय कभी नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)... इसलिए दुनिया के अर्थशास्त्रियों के पास भी इसका लेखा-जोखा करने का कोई मापदंड नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह बहुत बड़ा दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है और भारत ने कितना बड़ा निर्णय किया है, इसका भी ...(**व्यवधान**)... इसी प्रकार से जन-सामान्य का, देश की जन-शक्ति क्या होती है और इस सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों से मैं कहना चाहता हूं कि इस नोटबंदी के बाद समाजशास्त्री जरूर अध्ययन करेंगे। पहली बार देश में horizontal divide उभर कर आया है और जब मैं horizontal divide कहता हूं, तो जनता-जनार्दन का मिजाज एक तरफ और नेताओं का मिजाज दूसरी तरफ।

6.00 P.M.

ये जनता से इतने कटे हुए हैं कि पहली बार ...(**व्यवधान**)... हमें संतोष होना चाहिए, आम तौर पर सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जनता और सरकार by and large आमने-सामने होते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। ...(**व्यवधान**)... यह पहली ऐसी घटना है कि कुछ लोग तो उधर थे, लेकिन सरकार और जनता साथ-साथ थी। उसी प्रकार से इस बात का हम लोगों को गर्व होना चाहिए ...(**व्यवधान**)... हो सकता है, आपकी कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा और विश्व के सामने हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के सवा सौ करोड़ लोग ऐसे हैं, वे अनपढ़ हो सकते हैं, उन्हें शायद शिक्षा न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन कर रहे थे और जो रिपोर्ट कार्ड आप दे रहे थे कि ऐसा है, वह सब होते हुए भी यह देश है जो अपने भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है। चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी दल हो, यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं, जो अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए कष्ट झेलने को तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। इसलिए हमें भी इस बात को समझना होगा।

श्रीमती रेणुका चौधरीः ये सब आपकी बुराइयां भुगत रहे हैं, जब से आपकी सरकार आयी है ...(**व्यवधान**)...

श्री एम. वेंकैया नायडुः सर, यह क्या है?

श्री नरेंद्र मोदीः हम यह भी जानते हैं...

श्री एम. वेंकैया नायडुः सर, एक मिनट। सॉरी, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ...(**व्यवधान**)... Is the running commentary allowed in the House? मर्यादा है? संस्कार होने चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेंद्र मोदीः सभापति महोदय जी ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रेणुका चौधरीः डा. मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपने बहुत संस्कार दिखाए ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Silence please.

श्री नरेंद्र मोदीः आपकी अध्यक्षता के नीचे सब चल रहा है, हम तो ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदीः पिछले सत्र में डा. मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। यह बात सही है कि अभी शायद आपकी तरफ से एक किताब निकली है। उसका foreword डाक्टर साहब ने लिखा है। मैं जब आपकी रिपोर्ट देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला कि किताब किसी और ने लिखी, foreword उन्होंने लिखा है। ...(**व्यवधान**)... तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा कि शायद ...(**व्यवधान**)... यह बात बड़ी समझने की है कि पिछले करीब-करीब 30-35 साल से ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः आप प्रधान मंत्री हैं, पूर्व प्रधान मंत्री के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। वे आप से ज्यादा इकोनॉमी जानते हैं। ...(**व्यवधान**)... It is a breach of privilege …(*Interruptions*)… On this, we will not. How can he …(*Interruptions*)…

श्री सभापतिः शर्मा जी, बैठ जाइए।

श्री नरेंद्र मोदीः करीब-करीब 30-35 साल से ...(**व्यवधान**)... जो शब्द मैं बोला भी नहीं, वह समझ गए।

MR. CHAIRMAN : Why are you interrupting? Please sit down ...(*Interruptions*)…

श्री नरेंद्र मोदीः जो शब्द में बोला भी नहीं, उसका अर्थ समझ गए, यह बड़ी गज़ब की बात है। डा. मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधान मंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं और हिन्दुस्तान में पिछले 30-35 साल से भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा है ...(**व्यवधान**)... और निर्णायक भूमिका में रहा है। इस देश में अर्थ-जगत का शायद ही कोई ऐसा अकेला व्यक्ति होगा, जिसका हिन्दुस्तान की 70 साल की आजादी में आधे समय इतना दबदबा रहा होगा। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खासकर के हम राजनेताओं के लिए ...(**व्यवधान**). ... डा. साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है, इतना सारा हुआ और उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेन-कोट पहनकर नहाना, इस कला को तो डा. साहब ही जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता है। ...(**व्यवधान**)... इसलिए ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Order in the House, please. ...(*Interruptions*)... Please sit down. Everyone should go back to their places. ...(*Interruptions*)...You can't do this. All of you should sit down. ...(*Interruptions*)... Everyone, go back to your places. ...(*Interruptions*)... Go back to your places. ...(*Interruptions*)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग वापस अपनी जगह पर जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please go back. ...(*Interruptions*).. Please go back. ...(*Interruptions*)... I am appealing to hon. Members to sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: The Prime Minister is provoking, Sir. ...(*Interruptions*)... He is casting aspersions. ...(*Interruptions*)...

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)ः हम भी हाउस के मेम्बर हैं। ...(**व्यवधान**)... हमने सब सुना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः ये कहते हैं स्कैम ...(**व्यवधान**)... इसकी जांच होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: This is not fair. You can't do this, please. ...(*Interruptions*)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)....आप लोग वापस अपनी जगह पर जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: In protest, we are walking out, Sir. ...(*Interruptions*)...

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber*)

MR. CHAIRMAN: Please go back to your places. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आप अपनी बात कहकर सुनना नहीं चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी। ...(**व्यवधान**)... आपको सच्चाई बार-बार सुननी पड़ेगी। ...(**व्यवधान**)... आप सच्चाई सुनने से भाग रहे हैं! ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I appeal to hon. Members to sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आप बिना सच्चाई सुने भाग रहे हैं। सर, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... ये हमेशा सच्चाई सुनकर भागते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री रवि शंकर प्रसादः ये सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... इतनी गंदी बातें कही गईं, हमारे प्रधान मंत्री के बारे में । ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please maintain the decorum in the House. ...(*Interruptions*)...

श्री रवि शंकर प्रसादः हम लोग चुप रहे। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप लोग क्या कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I request you to go through the records. The Prime Minister was called a Hitler. The Prime Minister was called a Mussolini. The Prime Minister was called a...

MR. CHAIRMAN: Which record are you referring to?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It has happened in the House. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: If approached, action could have been taken. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The same party ...(*Interruptions*)... आप हमको सिखाइए मत। ...(**व्यवधान**)...

They are saying this inside the House and outside the House too. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please, वेंकैया जी, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am very sorry to say this, Sir. The Chair should keep in mind the sentiments of all sides of the House. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Are you suggesting that it is not? ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not saying that. The Chair should understand our pains. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I understand everybody's pains. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Prime Minister, who has been elected, is appreciated by the entire world. But, these people don't allow the Prime Minister to speak. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down, Venkaiahji? ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: These people participate and say anything. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Everybody should sit down. ...(*Interruptions*)... Now, go back to your places. Just go back to your places. Everybody, sit down. ...(*Interruptions*)... Please...(*Interruptions*)... That is enough.

MR. CHAIRMAN: Everyone should please sit down. ...(*Interruptions*).. Hon. Prime Minister, please.

श्री नरेंद्र मोदीः आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब "लूट" और "प्लंडर" जैसे शब्द प्रयोग किए थे, तब पचास बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि जब मर्यादा इधर लाँघते हैं, तो सुनने की भी तैयारी करें। हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं और यह हम संविधान की मर्यादाओं में रहकर करते हैं। हम लोकतंत्र का आदर करते हुए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार नहीं करना, यह कब तक चलेगा?

आदरणीय सभापति जी, यह बात सही है कि सामान्य जन को आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे और आज हम देश में देखते हैं कि कहीं एक छोटा-सा, कुछ अकस्मात ही प्रकरण हो जाए, तो भी दो-चार गाड़ियां जला दी जाती हैं, कहीं बस भी लेट आ जाए, तो भी एकाध, दो बसें जला दी जाती हैं। इसके बाय एंड लार्ज क्या प्रभाव होंगे, वह तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोज़मर्रा की घटनाएँ हैं। हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने ऐसी कोई घटना होने नहीं दी। हमें पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों की इस सामर्थ्य को गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हमें इसकी बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि तभी जाकर इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार से सोचते हैं।

मैं आज एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मसला ऐसा था — हमारी और सीताराम येचुरी जी की विचारधारा अलग है, इसलिए विचारों की प्रस्तुति अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक ऐसा विषय था — जब मैं सोच रहा था, तो मुझे इसकी पूरी कल्पना थी कि सीताराम जी और उनका दल इस काम में हमारे साथ रहेगा। उसका कारण था। उसका कारण यह था कि आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिर्मय बसु थे। उन्होंने 1972 में, वांचू कमेटी की रिपोर्ट हाउस में रखने की बड़ी मांग की थी और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी, आखिरकार वे एक कॉपी ले आए और उन्होंने खुद ही टेबल पर रखी। उन्होंने खुद ही, ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को प्राइवेट मेम्बर के नाते टेबल पर रखा। उस दिन उनका जो भाषण हुआ था, वह आज भी प्रासंगिक होता है। उन्होंने 26 अगस्त, 1972 को कहा था, "सर, 12 नवंबर, 1970 को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी

की प्राथमिक सिफारिशों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई हैं। उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है, इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, बल्कि डेढ़ साल तक दबाये भी रखा गया।" यह ज्योतिर्मय बसु जी ने 26, अगस्त, 1972 में कहा था। ...(**व्यवधान**)... दुबारा ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरीः आपने यह बात उठाई है, तो मैं कुछ कहूँ?

श्री नरेंद्र मोदीः दोबारा, 4 सितंबर, 1972 को लोक सभा में भाषण देते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, "मैंने विमुद्रीकरण और अन्य उपायों की सिफारिश की है। मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए..। लेकिन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार का चरित्र है, एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। यह मैं 1972 की बात कर रहा हूँ।

श्री सीताराम येचुरीः सर, आप जो यह कह रहे हैं, तो हमारी भी एक बात सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेंद्र मोदीः और यह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने 4 सितंबर, 1972 को कहा है। इतना ही नहीं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हरकिशन जी सुरजीत, उन्होंने 27 अगस्त, 1981 को इसी सदन में भाषण दिया और उसमें उन्होंने पूछा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए क्या सरकार वाकई कोई गंभीर कदम उठाना चाहती है? क्या सौ रूपए के नोट को बंद करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं? यह सवाल सुरजीत जी ने भी इसी सदन में 1981 में उठाया था। इसलिए खास करके लेफ्ट से मेरा आग्रह है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और आप देंगे, मैं आशा करता हूँ। आप अपने विचार व्यापक रूप से जरूर रखते रहे हैं, लेकिन यह काम ऐसा है, जिससे आप अलग हो ही नहीं सकते। आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है।

श्री सीताराम येचुरीः सर, आपने यह सवाल उठाया है, तो एक मिनट बोल लूं?

श्री नरेंद्र मोदीः अपनी बात आप बाद में कर लेना, आपके पास पूरी जिन्दगी पड़ी है, कहीं न कहीं से आ जाओगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरीः काले धन को रोकने के विरोध में हम कभी नहीं थे और न रहेंगे, सवाल यह है कि तरीका क्या है? आपने जिस तरीके से किया, उससे काला धन खत्म नहीं किया ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Sitaramji, please sit down.

श्री नरेंद्र मोदीः यह तो समय बताएगा। यह बात सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने कड़े फैसले लेना, आम तौर पर लोग मानते हैं कि पापुलिस्ट कदम लेना यह लोकतंत्र का स्वभाव बन जाता है, शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के फैसले करना स्वभाव बन जाता है, इसलिए इतने बड़े फैसले को समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, धीरे-धीरे लोग समझ जाएंगे। जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा फैसला देश का कितना बड़ा भला करने की संभावनाएं लेकर आया है और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

[श्री नरेंद्र मोदी]

सर, यहां पर डिजिटल व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई। मैं हैरान हूँ, सामने से जितने भाषण हुए, कहा कि इस देश में यह नहीं है, ढिमका नहीं है, फलां नहीं है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, टॉयलेट हैं तो पानी नहीं है, पता नहीं क्या-क्या बोला गया। मैं सोच रहा था कि ये जो बोल रहे हैं, वे क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि वे हिन्दुस्तान की 70 साल की सरकारों का रिकॉर्ड दे रहे थे। जो भी बोल रहे थे, यह नहीं है, तो यह 70 साल का रिपोर्ट कार्ड है और 70 साल में मेरा कंट्रिब्यूशन ढाई साल का ही है। आपने टॉयलेट बना दिया तो क्या मैंने ताला लगा दिया? आपने रोड बना दी तो क्या मैंने उखाड़ कर फेंक दी? आपने पानी का पाइप डाला था तो क्या मैंने आकर काट दिया? यह हकीकत है। कोई यह नहीं कहता कि हिन्दुस्तान के हर कोने में डिजिटल व्यवस्था है। कौन कहता है? सवाल यह है कि माइंडसेट बदलने के लिए जहां संभावना है वहां हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली शहर में, संभावना है, चलो दिल्ली से शुरू करो। हम लोग कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें। यह बीहेवियर चेन्ज का विषय है। अगर कोलकाता के लोगों के पास मोबाइल फोन है, कोलकाता में लोगों के पास अगर डिजिटल कनेक्टिविटी है, तो वहीं से शुरू करो। हो सकता है कि दूर-सुदूर बंगलादेश के बॉर्डर पर गांव में नहीं हो। यह कहना और फिर हम इस बात के तो गीत गाते रहते हैं कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, ढिमका कर दिया, जब उसको लागू करने की बात आई, तो तकलीफ हो रही है। आवश्यकता है, हम शब्दों का खेल खेलते हैं। हर कोई मानता है, किसी भी बच्चे को पूछो कि स्कूल डेली जाते हो? किसी को भी, आपकी संतानों को भी पूछूंगा, तो कहेंगे कि हां, डेली जाता हूँ। यह मुझे भी मालूम है, उसे भी मालूम है कि संडे को नहीं जाता है। सब को मालूम है। यह स्वाभाविक है। उसी प्रकार से देश में cashless का मतलब है धीरे-धीरे समाज को इस प्रकार की पेमेंट की दिशा में ले जाना। दुनिया में आज भी बड़े-बड़े समृद्ध देश चुनाव करते हैं, तो बैलेट पेपर छाप कर, ठप्पे मार कर चुनाव करते हैं। जिस देश को अनपढ़ माना जाता है, वह हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वह बटन दबा कर वोटिंग करता है। जिस दिन बटन दबाने की व्यवस्था आई होगी, किसी ने सोचा होगा कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी adopt कर सकता है! यानी हम अपने देश की शक्ति को कम न आँकें। हां, अगर हमें लगता है कि यह रास्ता ही गलत है, तब तो ठीक है, लेकिन असुविधा है, तकलीफ है, इसलिए छोड़ देना, यह सही नहीं है। असुविधा होगी, व्यवस्थाएँ कम होंगी, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या दुनिया में कोई देश है? दुनिया के कई देश, मैं हैरान हूँ, आनन्द शर्मा जी कह रहे थे, आपको आश्चर्य होगा, कोरिया ने डिजिटल पर जाने के लिए जो incentive scheme बनाई है, यह इतनी बड़ी मात्रा में आई। ये कह रहे हैं कि आप करोड़ों रूपए डिजिटल को promote करने के लिए खर्च कर रहे हैं। अब जो 'भीम' ऐप बनाया गया है, 'भीम' ऐप में एक नए पैसे का खर्च नहीं है। इससे बिना खर्च transaction हो रहा है। किसी बैंक को एक रूपए का कोई कमीशन नहीं जाता है। इसलिए दुनिया paper less, premises less banking की तरफ जा रही है, इसमें भारत के पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। हां, हो सकता है, हमारी व्यवस्थाएँ कम होंगी, तो साल-दो साल और ज्यादा लगेंगे, 5 साल और लगेंगे, लेकिन शुरू करना या यह दिशा गलत है, यह विचार मैं समझता हूँ कि उपयुक्त नहीं होगा। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसको promote करने के लिए अपने-अपने इलाके में भी लोगों को हमें समझाना चाहिए और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए।

अब देखिए, हमारे देश में रेलवे है। इसमें सामान्य मानव भी जाता है। आज रेलवे में 60 से 70 प्रतिशत booking online होने लगी है। उनकी पेमेंट online होती है और अगर वे टिकट cancel करते हैं, तो पैसा online वापस जा रहा है। आज बहुत से परिवार हैं, जो शहरों में रहते हैं। अगर उनको बिजली का बिल भरना है, तो पहले बिजली का बिल भरने के लिए आधे दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी, आज वह घर आकर रात को 12 बजे अपने मोबाइल फोन से बिजली के बिल की पेमेंट दे रहा है। सुविधा बढ़ती चली जा रही है। अगर यह सुविधा वैज्ञानिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से मिलती है, तो अच्छी बात है। हां, हमें उसकी कमियों की चिन्ता जरूर करनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी में कोई कमी आती है, तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन यह कल्पना ही गलत है, अगर हम यह negativity लेकर चलेंगे, तो हम देश का कोई भला नहीं कर सकते हैं।

रूपे कार्ड के बारे में अभी अरूण जी बता रहे थे। इस देश में जन-धन एकाउंट के साथ 21 करोड़ लोगों को रूपे कार्ड दिए गए हैं। आपको अंदाज नहीं है कि इसकी ताकत क्या होती है। आम तौर पर जेब में यह कार्ड होना एक वर्ग के लिए बड़ा prestigious हो गया है। पेमेंट करना है, तो कार्ड से करना है। यह भी हवा बन गई है कि यह गरीब का तो विषय ही नहीं है। अभी मुझे अनंत कुमार जी बता रहे थे कि वे बेंगलुरू से आ रहे थे, तो उनके साथ कोई IT Professional बैठे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर की एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि demonetization से उनका ड्राइवर बहुत खुश है। उन्होंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बताया कि उसने कहा कि देखिए, आज कोई बड़ा आदमी कार्ड रखता है, मैं भी कार्ड रखता हूँ। वह उनको कार्ड दिखाने लगा। उसको बड़ा आनंद था। अब देखिए, इससे समाज के सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी एक बदलाव की व्यवस्था आई है। इससे एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। जिसके घर में एक साइकिल भी नहीं आती है, वह खुशी से समा नहीं पाता है, जब उसके पास मोटरसाइकिल आ जाती है। जिसके पास स्कूटर हो, अगर वह छोटी सी कार लाता है, चाहे पुरानी भी लाता है, तो वह गर्व करता है। समाज के छोटे-छोटे लोगों के जो aspirations हैं, उन aspirations को पूरा करने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए।

अब Direct Benefit Transfer से कितना बड़ा फायदा हुआ है। मैंने उस सदन में विस्तार से इसके बारे में कहा है। Direct Benefit Transfer के द्वारा हम करीब-करीब 50 हजार करोड़ रूपए, जो कभी leak होते थे और हर वर्ष होते थे, अब तक बचा पाए और आगे पता नहीं, कितने बचा पाएँगे। Scholarship जैसी सुविधा में एक ही व्यक्ति छः जगह पैसे लेता था। विधवा पेंशन, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वह विधवा भी हो गई और चेक भी कट रहा था। Direct Benefit Transfer Scheme के कारण ये जो leakages थे, जो बिचौलिए ले जाते थे, जिनसे देश का बहुत बड़ा खजाना लूटा जा रहा था, उन पर रोक लगी है। इसके कारण Direct Benefit Transfer Scheme का भी फायदा हुआ है, इसलिए हमें digital payments को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए हम जितना प्रयास कर सकें, करते रहना चाहिए। सरकार ने इसके लिए अपनी व्यवस्था को विकसित किया है। POS machines की आवश्यकता को देखते हुए, बहुत तेज़ी से POS machines बढ़ाई जा रही हैं। Online payments को आगे बढ़ाने के लिए ई-वॉलेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही Internet Banking को बढ़ावा देने की दिशा में काम चल रहा है।

इतनी तेजी से technology develop होगी, अब सिर्फ 'आधार' के आधार पर सब काम होंगे। उसके लिए mobiles की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हर व्यक्ति अपनी पेमेंट कर पाएगा, अब वे

[श्री नरेंद्र मोदी]

दिन दूर नहीं हैं। इन व्यवस्थाओं को या तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करें और इन स्कीम्स को व्यवहार में लाने का प्रयास करें।

'BHIM App' के माध्यम से भारत सरकार की छत्रछाया में एक बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनी है। हम BHIM App को पॉपुलर करेंगे। इससे किसी व्यापारी या बाहर की किसी एजेंसी को कोई लेना-देना नहीं होगा, यह एक सीधा-सीदा और enabled platform है, जिसका लाभ लोग ले सकते हैं। हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए।

अब देखिए, जो ड्राइवर्स हाईवेज़ पर जाते हैं, हम जानते हैं कि टोल पर देर तक रूकने के कारण पेट्रोल और डीज़ल का कितना व्यर्थ खर्चा होता है। 8 नवम्बर के बाद उस पर भी बल दिया गया है, ताकि टोल टैक्स देने के लिए ड्राइवर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और Radio-frequency Identification (RFID) के ज़रिए टोल-टैक्स दें। पहले इक्का-दुक्का लोगों के पास यह व्यवस्था थी। इतने कम समय में, अब करीब-करीब 20% ट्रैफिक में RFID के द्वारा पेमेंट ली जाती है। कार आती है, सीधे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, टैक्स डिपॉज़िट हो जाता है और कार चली जाती है। अब उसको देर तक वहां रूकना नहीं पड़ता है। अगर यह काम और आगे बढ़ेगा, तो देश का कितना पेट्रोल बचेगा। इसी प्रकार आज पेट्रोल पम्पस पर करीब-करीब 29%-30% लोगों ने digital currency से काम करना शुरू कर दिया है। हमने चंद्रबाबू नायडु जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट आई है। अब उस पर अध्ययन हो रहा है और जल्दी ही उसकी फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। हम बदलाव के लिए तैयारी करें।

एक विषय है, banking system. इस पर अगर आप कुछ भी कहते हैं, तो उसके जवाब में मैं यह कहूंगा कि वह पुराने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड है। इस सरकार ने सबसे पहले छः Debt Recovery Tribunals की रचना की और बैंकों में जो Debt बकाया है, उसके बारे में सरकार ने initiative लिया।

बैंकों में जो appointments होती थीं, उनके लिए कोई नियम नहीं था, यह काम एक घिसी-पिटी व्यवस्था के तहत ऐसे ही चल रहा था। इस सरकार ने एक Bank Board Bureau बनाया, जो independent agency है और अब वही बैंकों में रिक्रूटमेंट करती है। उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने इस दिशा में काम करके banking व्यवस्था में professionalism लाने का प्रयास किया है।

फाइनेंस जगत, बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी वर्ल्ड, इन सबकी दो दिन की एक round table conference आयोजित की गई। उन्होंने विस्तार से इस विषय पर आत्ममंथन किया, चिन्तन किया कि हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था को global level के standard तक कैसे लाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी कमियों को समझा और उसको ठीक करने का प्रयास किया।

रिजर्व बैंक की गरिमा के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मुझ पर हमला हो, हमारी पार्टी पर हमला हो, सरकार पर हमला हो, यह बहुत स्वाभाविक है, यह तो चलता रहेगा, लेकिन रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक के गवर्नर को इसमें घसीटने का कोई कारण नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस की मान-मर्यादा कायम रखने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए। इनसे पहले जो गवर्नर थे, उनके खिलाफ भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन मैंने उसका भी

विरोध किया था कि यह शोभा नहीं देता है। ऐसी चीज़ों को विवादों से परे रखना चाहिए, बाकी सरकार की व्यवस्थाएं तो चलती ही रहेंगी। अर्थव्यवस्था चलाने में रिजर्व बैंक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसकी credibility की दिशा में हम लोगों का सक्रिय सकारात्मक योगदान होना चाहिए, लेकिन जो लोग सरकार पर आरोप लगाते हुए रिजर्व बैंक की गरिमा पर भी आरोप लगाते हैं, मैं उनसे आज बड़े दुःख के साथ एक बात कहना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने 2008 में एक किताब लिखी थी, 'Who Moved My Interest Rate'. उस किताब में उन्होंने लिखा था, "तत्कालीन वित्त सचिव के तहत एक Liquidity Management Committee को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय से मैं नाराज़ और परेशान था।..." महोदय, उन्होंने लिखा है कि चिदम्बरम ने स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्र में ओवरस्टैप किया था। लिक्विडेट मैनेजमेंट पूरी तरह से रिजर्व बैंक का फंक्शन है। इस विषय पर उन्होंने मुझ से परामर्श भी नहीं किया, बल्कि अधिसूचना जारी करने के बारे में मुझे बताया तक नहीं था। मुझे क्या पता था कि यह निर्णय, मेरे कार्य-काल के अंतिम वर्ष में, हम दोनों के बीच, असहज़ संबंध के लिए टोन सैट करेगा। रिजर्व बैंक के एक्स-गवर्नर ने पुरानी सरकार पर गम्भीर आरोप लगाया है और अपनी किताब में छापा है। अभी तक इसका किसी ने जवाब नहीं दिया है। अब मैं बोल रहा हूं, इसलिए कुछ कहेंगे, तो अलग बात है। यह बात सही है कि आज हमें ये उपदेश देते हैं, जरा ये भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मैं इस बात को मानूंगा कि इसे हम राजनीति से परे रखें और इस इंस्टीट्यूशन का गौरव बनाए रखने की दिशा में प्रयत्न करें।

सभापति जी, हमने क्या किया है, वह मैं बताना चाहता हूं। आरबीआई की ताकत बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय किए हैं। हमने आरबीआई एक्ट में संशोधन कर के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की है। कई वर्षों से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन इसे कोई नहीं कर रहा था। हमने इसकी स्थापना की। इस समिति को मॉनिटरी संचालन की पूरी स्वायत्तता दी गई है। इस समिति के प्रमुख आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के दो अधिकारियों के अलावा तीन विशेष इसके सदस्य हैं। इस समिति में केंद्र सरकार का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है। मॉनिटरी पॉलिसी बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी स्वायत्तता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन इस सरकार ने वह स्वायत्तता आरबीआई को दी है और उसके कारण आरबीआई की ताकत को बढ़ावा मिला है।

महोदय, यह बात सही है कि कई विषयों पर यहां चर्चाएं हुई हैं। कोई सरकार सोने के लिए तो नहीं आती है। पहले भी जो सरकारें आई थीं, उन्होंने भी कुछ न कुछ तो करने का प्रयास किया होगा। हम यह तो नहीं कहते कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इस बारे में तो मैं लाल किले से बोला हूं। मैंने लाल किले की प्राचीर से बोला, वह हिन्दुस्तान के किसी और प्रधान मंत्री ने नहीं बोला। मैंने कहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से जितनी भी सरकारें आईं, जितने भी प्रधान मंत्री आए, जितने लोगों ने काम किया है, उन सबका योगदान है, तब देश आज यहां पहुंचा है। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमारा नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। उनको पसंद नहीं है कि किसी ने कोई काम किया है, तो उसका उल्लेख तक करें। इतिहास गवाह है। यह बात सही है कि इस सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर बहुत काम किया है। देखने में ये छोटे-छोटे निर्णय लगेंगे, लेकिन इन निर्णयों ने सामान्य मानवों की ताकत को बहुत बढ़ावा दिया है।

[श्री नरेंद्र मोदी]

महोदय, पहले अफेडेविट को अटेस्ट करने की प्रथा थी। एमपी के घर, एमएलए के घर, कॉरपोरेटर के घर लोग ठप्पा लगवाने के लिए आकर खड़े हो जाते थे, क्यू लग जाती थी। मैं देखता था कि कोई पियून बैठता या कोई साथी कार्यकर्ता बैठता था और वह ठप्पे मार देता था। हमने उसे समाप्त कर के सैल्फ-अटेस्टेशन की व्यवस्था कर दी और उसके कारण वे उस संकट से बच गए, क्योंकि जब उसकी फाइनल अपॉइंटमेंट होगी, तो वह अपनी ओरिजनल कॉपी लेकर जाएगा। आज तो जेरॉक्स का जमाना है। इस सबको करने की क्या जरूरत है। नॉन-गैजेटेड पोस्ट के लिए हमने इंटरव्यू खत्म कर दिए। अब टैक्नोलॉजी के द्वारा तय होगा और जो उसकी मेरिट होगी, उसके आधार पर उसे नौकरी मिलेगी। उसके कारण पहले जो करप्शन होता था, वह रूक गया है।

महोदय, हमने 1100 से अधिक कानूनों को खत्म किया है। इन्हीं दो सालों में खत्म किया है। सीनियर पोस्ट पर नियुक्ति के बारे में कई अखबारों ने आर्टिकल लिखे हैं कि पहली बार मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट हो रही हैं। पुरानी प्रक्रिया और मेरा-तेरा, सब चला गया है और इस पर कई न्यूट्रल अखबारों ने बहुत अच्छे आर्टीकल भी लिखे हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के द्वारा लीकेजेज़ को रोका गया है। पहले यदि कोई कंपनी रजिस्टर करनी होती थी, तो सात-सात दिन, 15-15 दिन और दो-दो महीने लगते थे। आज 24 घंटे में कंपनी रजिस्टर हो सकती है, यह व्यवस्था की है। पहले पासपोर्ट बनवाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आज पासपोर्ट एक हफ्ते के भीतर देने की व्यवस्था की है। अब पोस्टल के जो हैड ऑफिसेस हैं, उन्हें भी पासपोर्ट ऑफिस में कन्वर्ट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसका भी लाभ सामान्य मानवों को मिलने वाला है और उस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। हम यह भी जानते हैं कि कोयले की नीलामी कितना बड़ा विषय था। सरकार ने उसको आसानी से लागू कर दिया, पारदर्शिता को लाया। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, जिसकी चर्चा अभी काफी नहीं हुई है, लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ। सरकार की खरीद करने की जो परम्परा होती है, उसमें हम लोगों ने GeM को लांच किया है– Government e-Marketplace. इस व्यवस्था को वर्ल्ड बैंक के South Asia Procurement Innovation Award से भी सम्मानित किया गया है। अब उसमें दुनिया में जिसको भी सरकार को देना होगा, वे ऑनलाइन आते हैं, अपनी लिस्ट रखते हैं और सरकार उसमें से तय कर सकती है। आर्थिक लाभ भी हुआ है और यदि 5,000 रूपये से ज्यादा का पेमेंट करना हो तो इस GeM के माध्यम से कर सकते हैं। उस दिशा में हमने व्यवस्था की है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ गुड गवर्नेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से एक पारदर्शिता लाने की दिशा में हम बड़ी सफलता पाए हैं। इस सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक नयी योजनाएँ बनाई हैं। आप हर योजना में देखिए। 'उज्ज्वला योजना' हम जानते हैं कि गैस के सिलेंडर का क्या जमाना था। एमपीज़ को 25-25 कूपंस मिला करते थे और उन 25 कूपंस को लेने के लिए लोग कतार लगाते थे, वे भी दिन थे। 2014 के चुनाव में 9 सिलेंडर दें या 12 सिलेंडर दें, उसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा गया था। इस सरकार की कार्यसंस्कृति में कितना फर्क है! गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा, ये सपने में कभी सोच नहीं सकती थीं, अब तक करीब-करीब 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। इसे 5 करोड़ परिवारों तक पहुँचाने का पूरा इरादा है। देश में 25 करोड़ गरीब परिवार

हैं, उनमें से 5 करोड़ गरीब परिवारों को इसे पहुँचाने का प्रयास है। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' है। महिलाओं के नाम पर घरों के रजिस्ट्रेशन की कानूनन व्यवस्था की गई है। 'मनरेगा' में काम करने के लिए आज 55 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जो पहले 40, 42 या 45 प्रतिशत हुआ करती थीं। 'मुद्रा योजना'—मुद्रा योजना में बैंक से पैसे दिए जाते हैं, without guarantee दिए जाते हैं। पैसे लेने में 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यानी entrepreneur के रूप में हमारे देश की महिलाएँ इसके साथ जुड़ रही हैं। 'पंडित दीनदयाल अन्त्योदय योजना'— Self Help Group के काम दक्षिण भारत में कुछ मात्रा में चलते थे, लेकिन पूरे भारत में और Eastern India में उसको बढ़ावा देने की दिशा में भी हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। पूरे हिन्दुस्तान में गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रूपये प्रसूता में IMR-MMR के लिए, इस बात को लागू करने का काम हुआ है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को बहुत बड़ी मात्रा में स्वीकृति मिली है। वह एक सामाजिक आन्दोलन बना हुआ है। 'सुकन्या समृद्धि योजना'— बच्चियों के नाम पर एक करोड़ अकाउंट्स खुले हैं और 11,000 करोड़ रूपये जमा हुए हैं, जो इनको भविष्य के लिए एक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। 'महिला शक्ति केंद्र'- 500 करोड़ की लागत से 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में इसकी स्थापना हुई है।

'मिशन इंद्रधनुष' — बच्चों का टीकाकरण नहीं होता था। सरकार चलाती थी, टीकाकरण के कार्यक्रम होते थे। 55 लाख बच्चे ऐसे ध्यान में आए, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। 'मिशन इंद्रधनुष' के कारण उन बच्चों को खोजा गया और उनकी जिन्दगी बचाने की दिशा में काम किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र में — यहां पर मैं हैरान था — स्वच्छता का मजाक उड़ाया जा रहा था। क्या कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम में से कोई नहीं है, जो गंदगी में रहना चाहता है। हम यह भी जानते हैं कि स्वच्छता behaviour का इश्यू ज्यादा है, infrastructure का तो उसके साथ आता है। मैं कहूँगा कि हम राजनेता कभी-कभी कम पड़ रहे हैं। मैं इस देश की मीडिया का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि स्वच्छता के आन्दोलन को उसने उठा दिया। आज सब मीडिया के द्वारा स्वच्छता के लिए ईनाम दिए जा रहे हैं, स्वच्छता के सम्बन्ध में आज हिन्दुस्तान भर में फंक्शंस आयोजित किए जा रहे हैं। वरना मीडिया सरकार के किसी भी कार्यक्रम की निगेटिव रिपोर्टिंग करे, वह बहुत स्वाभाविक है। यह कार्यक्रम एक ऐसा अपवाद है, जिसको सरकार से भी और राजनेताओं से भी दो कदम आगे मीडिया के लोग ले गए हैं और स्वच्छता को एक आन्दोलन बनाने की दिशा में प्रयास किया है। मैं इस सदन के माध्यम से उनका अभिनन्दन करता हूँ और यहां कोई खड़ा होकर कहता है कि टॉयलेट है, पानी नहीं है। महात्मा गांधी जी भी इस बात के लिए बड़े आग्रही थे। मुझे तो डर लगता है कि कहीं आज महात्मा गांधी होते और स्वच्छता की बात करते, तो क्या हम लोग यही भाषा बोलते? क्या यह हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या समाज में बदलाव लाने के लिए कोई सकारात्मक चीज कर ही नहीं सकते हैं? क्या हर चीज में हम विरोध करेंगे? मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में sanitation coverage, जो पहले 42 परसेंट था, इस आंदोलन के बाद वह 60 परसेंट पहुंचा है। हम जब भी टॉयलेट की बात करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं गांव की महिलाओं या शहर में भी झुग्गी-झोंपड़ी में जो महिलाएं रहती हैं, उनको कितनी पीड़ा होती थी, जब तक अंधेरा नहीं होता, तब तक वे शौचालय नहीं जा सकती थीं। हमें गर्व होना चाहिए, यह 'तू-तू, मैं-मैं' का विषय नहीं है, लेकिन जब इसको लेकर कोई मज़ाक उड़ाते हैं, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। यह मज़ाक का विषय नहीं हो सकता है।

[श्री नरेंद्र मोदी]

महिलाओं की सुरक्षा के लिए Universalisation of Women Helpline 181, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा को शुरू किया गया। 18 स्टेट्स एण्ड यूटीज़, इन्होंने इस महिला हेल्पलाइन व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। महिलाओं की पुलिस में भर्ती 33 परसेंट और कुछ राज्यों ने भी स्वीकार किया है, यूटीज़ के अंदर यह compulsory कर दिया गया है। हरियाणा ने एक नया प्रयोग किया है, जिसको हिन्दुस्तान में और लोग करें, मैंने सबके सामने इसका प्रेजेंटेशन किया है। उन्होंने महिला पुलिस वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क खड़ा किया है, जो इस प्रकार से लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है... एक पैनिक बटन की टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने लेकर आने वाले हैं।

किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसके कारण.... अब सबसे बड़ी बात, 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना', हमें पसंद आए या न आए, लेकिन किसान को सुरक्षा देनी है, तो हमें उसको उसकी इन्कम के assurance के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे यहां इरिगेशन की सुविधा बहुत कम है, प्राकृतिक संसाधनों पर ही वह डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में अगर वह बो नहीं सकता है तो भी, और कटाई के बाद भी अगर बरबाद होता है तो भी, अगर इंश्योरेंस मिलता है और मुझे खुशी है कि कुछ प्रोग्रेसिव राज्यों ने 40-40, 50-50 प्रतिशत किसानों का इंश्योरेंस का काम किया है और सरकार ने भी करीब-करीब किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इस 'फसल बीमा योजना' को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है। इसमें पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ राज्य इसमें बहुत पीछे हैं, यह चिंता का विषय है। इसको आगे बढ़ाना है। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय दिया जाए।

श्री नरेंद्र मोदीः बाद में करते हैं, सर जी, एक बार हो जाए। आपको तो मैं जिन्दगी भर सुनूंगा, आप बैठिए न।

नई फर्टिलाइजर पॉलिसी, यूरिया का उत्पादन, देखिए नीम कोटिंग, नीम कोटिंग के कारण दो महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं, एक तो जमीन को फायदा हो ही रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन पहले किसान के नाम से सब्सिडी कटती थी, बिल किसान के नाम से फटता था, लेकिन वह केमिकल इंडस्ट्री में raw material के रूप में चला जाता था। जो सिंथेटिक मिल्क बनाते थे, वे भी यूरिया का उपयोग करते थे। 100 परसेंट नीम कोटिंग करने के कारण जमीन के सिवाय उसका कहीं उपयोग संभव ही नहीं रहा है। इससे चोरी रूक गई है, आज यूरिया की ब्लेकमेलिंग नहीं हो रही है। यूरिया नहीं मिल रहा है, ऐसी किसी चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं आती है, यूरिया के लिए कतार नहीं लगती है, यूरिया के लिए किसी को परेशानी नहीं हो रही है। छोटे से परिवर्तन भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वह आप देख सकते हैं।

हमारे देश में दाल का उत्पादन, पल्सेज़, इस सरकार ने उसको प्रमोट करने की दिशा में प्रयास किया है और उसका परिणाम यह है कि आज करीब-करीब 50 से 60 प्रतिशत वृद्धि की संभावना इस बार पैदा हुई है। हमारे देश के किसानों ने सरकार के आह्वान को स्वीकार किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इस काम को उन्होंने किया है।

e-NAM, electronic market, 500 मंडियों में, अब किसान जहां भी ज्यादा दाम पर माल बिक सकता है, वह इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेच सकता है। 500 मंडियों में मोबाइल फोन के द्वारा आज मेरा किसान अपना व्यापार कर सके, ऐसी स्थिति बनी है। करीब 250 मंडियों ने इस काम को पूरा कर दिया है। राज्यों को कुछ कानून बदलने थे, कुछ राज्यों ने कानून बदले हैं, लेकिन हम फूड प्रोसेसिंग जानते हैं, हमारे किसान को लाभ तब होगा, जब हम फूड प्रोसेसिंग पर बल देंगे। सरकार ने 100 परसेंट एफ.डी.आई. एलाउ की है ताकि फूड प्रोसेसिंग को मदद मिले और value addition हो, हमारे किसानों को ज्यादा इन्कम हो और उस दिशा में काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं।

आदिवासियों का सशक्तीकरण – करीब 2800 ब्लॉक्स का कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ संबंध रहता है। हमने पहली बार एक ट्राइबल सब-प्लान बनाकर राशि तो बढ़ा दी, लेकिन वनबंधु कल्याण योजना के तहत एक comprehensive plan बनाया, ताकि उसका outcome दिखाई दे। उस दिशा में काम करने का हमने सफल प्रयास किया है। Forest Rights Act को मजबूती से लागू करने की दिशा में हमने काम किया है और tribal areas में पहली बार, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मिनरल्स हैं, माइनिंग हैं, वे ज्यादातर tribal बैल्ट में हैं, चाहे कोयला हो, आयरन हो या कुछ और हो, लेकिन वहां उन्हें लाभ नहीं मिलता था। पहली बार सरकार ने District Mineral Foundation बनाया और वहां खदानों से जो कुछ निकलता है, उस पर टैक्स लगाया। मुझे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उनके 7 जिले ऐसे हैं, वहां जो खनिज निकलता है, हमारे District Mineral Foundation बनाने के कारण, उन जिलों के विकास के लिए, उन्हें अब extra budget की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी मात्रा में राशि उन गरीब आदिवासियों के काम आने वाली है, जिसका हमने इंतजाम किया है। हमने जो Rurban Mission चलाया है, उसका सबसे बड़ा लाभ आदिवासी क्षेत्रों में होने की संभावना है। आदिवासी इलाके में बड़ा Marketing place develop होना चाहिए। यदि Marketing place develop होता है तो वहां एजुकेशन सिस्टम आता है, medical facilities आती हैं, दूसरी entertainment की सुविधाएं, मार्केट की सुविधाएं आदि आती हैं। धीरे-धीरे अगल-बगल के पचासों गांवों और पूरे इलाके का वह केंद्र बन जाता है। Rurban के द्वारा tribal belt में 300 ऐसे नए शहर बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और यह आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत बड़ा काम होगा। ...(**व्यवधान**)...

इसी प्रकार, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, स्वच्छता देश में एक जन-आन्दोलन बनना चाहिए और जन-आन्दोलन बनाने की दिशा में हम सबका कोई-न-कोई योगदान होना चाहिए। जब से हमने स्वच्छता के लिए independent agencies के द्वारा प्रचार करना शुरू किया है, उससे शहरों के बीच में स्पर्धा शुरू हुई है। एक शहर अगर आगे गया, तो दूसरा शहर उस शहर से कम्पीट करने लगता है कि देखो, वह शहर तो आगे चला गया, हम क्यों सफाई नहीं कर रहे हैं? धीरे-धीरे यह सोच नीचे तक जाने लगी है। हम लोगों को इस पर बल देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे देश में जितनी political parties हैं, सभी political parties को कहीं-न-कहीं सरकार चलाने का इन दिनों अवसर मिला है, कोई नगर पालिका में होंगे, कोई जिला पंचायत में होंगे, कोई राज्य में होंगे। अपनी पार्टी की सरकारों में जहां आपको सेवा करने का अवसर मिला है, आप उनमें भी तो competition चलाइए। Communist-ruled जितने शहर हैं, उनके बीच स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा कीजिए, Communist-ruled जितनी District Panchayats हैं, उनके बीच स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा

[श्री नरेंद्र मोदी]

कीजिए। इससे एक वातावरण बनेगा। बीजेपी ruled जितनी स्टेट्स होंगी, वहां की नगर पालिकाएं कम्पीटीशन करें। एक बार ऐसे कम्पीटीशन को हम आगे बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा स्वच्छता अभियान सफल होगा। यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह जन-आन्दोलन बनना चाहिए। यह युग की आवश्यकता है, behavioral change की आवश्यकता है। हम जानते हैं और World Bank का record कहता है कि अस्वच्छता के कारण, हैल्थ सुविधाएं देने के कारण हमारे ऊपर करीब ढाई लाख करोड़ रूपए का बोझ पड़ता है। अगर हम केयर करें तो देश की इतनी बड़ी राशि बचा सकते हैं। यह World Bank का रिकॉर्ड है, हिन्दुस्तान के संबंध में। एक गरीब आदमी पर एक साल में करीब 7000 रूपया खर्च आता है और गंदगी से बीमारियां आना बहुत स्वाभाविक है। हम इसे बचा सकते हैं।

बच्चों को हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, इसे हर कोई मानता है, लेकिन जब हम ऐसा कहें तो कोई कहेगा कि वहां पानी नहीं है, वहां नल नहीं है, वहां यह नहीं है, वह नहीं है। बच्चा किसी कुएं पर जाएगा तो कहेंगे कि ऐसे हाथ नहीं धोते हैं। यह जो सोच है, इसी सोच ने देश को यहीं दबोच कर रखा हुआ है। आप कुछ सोचें तो सही, कुछ निकले तो सही। कठिनाइयां आयेंगी तो रास्ते भी निकलेंगे लेकिन हम घर में बैठकर अपने बच्चों को समझाने की बजाए कहें कि वहां यह नहीं है, वह नहीं है – ऐसे देश बदलता नहीं है। ऐसी मानसिकता से हम देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। इस मानसिकता से हमें बाहर आना चाहिए। दुनिया में हम अपने पड़ोस के देशों को देखें। चाहे हम साउथ कोरिया को देखें, मलेशिया को देखें, थाइलैंड को देखें या सिंगापुर को देखें, वे छोटे-छोटे देश हैं, उन्होंने स्वच्छता के लिए 15-15 साल लगा दिए और आज वे हम लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में नज़र आते हैं। हम हिन्दुस्तान में वैसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारा भी तो सपना होना चाहिए कि अगर छोटे-छोटे देश इसमें सफल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, किसी शायर ने कहा है–

"शहर तुम्हारा, क़ातिल तुम, शाही तुम, हाकिम तुम,
मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा।"

लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें से हम ज़रा बाहर आएँ। मैं एक और विषय कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। "एक भारत, श्रेष्ठ भारत", इस काम को हमने 31 अक्तूबर को सरदार पटेल की जयंती पर लांच किया है। हमारे देश में दुनिया के किसी राज्य के साथ सिस्टर स्टेट बनना, सिस्टर सिटी बनना, यह तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन हमारी अपने ही देश के अलग-अलग लोगों से मिलने की आदत नहीं बनी। हमने इस प्रकार से कर दिया, जिसके कारण कई राज्यों को लगने लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है। हमें अपने देश के पोटेंशियल को पकड़ना चाहिए। हमने "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" कार्यक्रम के तहत इसके लिए कोशिश की है और मैं चाहूँगा कि इस सदन में जो लोग हैं, वे इसको समझने में और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। जैसे, दो राज्यों के बीच में एमओयू करते हैं। अभी 12 राज्यों ने शायद एक-दूसरे के साथ यह कर लिया है, जैसे हरियाणा और तेलंगाना ने किया है। हरियाणा में तेलुगु भाषा के 100 सेंटेंसेज़ हरियाणा के लोग बोलना सीखें, जैसे– हॉस्पिटल कहां है, रिक्शा कहां मिलेगा, होटल कहां है, बस स्टेशन कहां हैं, पुलिस थाना कहां है आदि। यह उनको सीखने को मिलेगा और तेलंगाना के

लोग हरियाणा की भाषा सीखें। हरियाणा में कभी तेलंगाना का फिल्म फेस्टिवल हो, कभी हरियाणा का फिल्म फेस्टिवल तेलंगाना में हो। उनके बीच क्विज़ कॉम्पिटीशन हो। तेलंगाना की क्विज़ कॉम्पिटीशन में हरियाणा के बच्चे हिस्सा लें और तेलंगाना के बच्चे हरियाणा की क्विज़ स्पर्धा में भाग लें। इस प्रकार, यह एक प्रकार से देश को जानने का और देश से जुड़ने का अभियान है और इसको हम जितना बढ़ाएँगे, उतना ही अच्छा होगा। कभी-कभी किसी चीज़ के लिए हिन्दी भाषा में शब्द भी नहीं होते, लेकिन तमिल में उसके लिए अच्छा शब्द होता है, लेकिन उससे हम परिचित नहीं हैं। मराठी में बढ़िया शब्द होता है, बांग्ला में बहुत बढ़िया शब्द होता है, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं हैं। हमारे देश की जो इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को जोड़ने की दिशा में "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" का एक अभियान चलाने की दिशा में प्रयास चल रहा है।

सभी आदरणीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, उनके प्रति मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे इसको समर्थन देने के लिए अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रपति जी के उद्‌बोधन को अपना समर्थन देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः शरद जी, आप कुछ कहने वाले थे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, please allow us. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, please allow us. We listened to the Prime Minister for 90 minutes. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापतिः शरद जी, आप कुछ कह रहे थे? ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः सर, मैं यह कह रहा था कि जब किसानों की बाबत प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे ...(**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O'BRIEN: We listened to the Prime Minister for 90 minutes without disruption. Please give us 90 seconds. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, normally, in the Motion of Thanks discussion on the President's Address, this kind of a discussion doesn't take place. It takes place in this House in the debates.

MR. CHAIRMAN: Because the hon. Prime Minister had mentioned that he could intervene after he completes. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादवः अरूण जी, उस समय आप नहीं थे। ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कोई क्लैरिफिकेशन की परम्परा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, when our names are taken, when our parties are referred to, when our politics is referred to, we have this opportunity to explain. ...(*Interruptions*)... This cannot be denied. That is our democratic right.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, even then राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कोई क्लैरिफिकेशन की परम्परा नहीं है। **...(व्यवधान)...**

SHRI SITARAM YECHURY: This is wrong because we have this right. Whenever there is a reference made to any particular name or any particular party, that person or that party representative gets the chance to clarify. ...(*Interruptions*)... That is why, when we were asked not to interrupt, we did not. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I shall now take up... ...(*Interruptions*)...

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): ये तो हर विषय पर बोलते हैं। **...(व्यवधान)...**

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, every time, they are doing ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: It was said, later, they will clarify. The Prime Minister said... ...(*Interruptions*)... This is now that 'later'. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: We will follow the convention of the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: With all respect to the hon. Prime Minister following the true principles of Parliamentary democracy, we did not stand up once. We heard him uninterrupted because... ...(*Interruptions*)... No, Sir, one minute. ...(*Interruptions*)... Sir, the Prime Minister was telling the people of the country to take the credit card and eat the credit card for lunch. ...(*Interruptions*)... दाल, रोटी, चावल नहीं खाएगा तो प्लास्टिक खाएगा क्या? **...(व्यवधान)...**

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, please do not allow this now. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. That is enough. ...(*Interruptions*)... That is enough. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we did not interrupt... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. gentlemen, please. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we want... ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you had allowed, you means the Chair... ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: It was said, Sir. ...(*Interruptions*)... Otherwise, it is... ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: The Chair had allowed... ...(*Interruptions*)... The Prime Minister will reply to the debate on the Motion of Thanks. There is no reply. ...(*Interruptions*)... It is only a monologue delivered as an election campaign. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANTHKUMAR: Hon. Chairman, Sir, please do not... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: He has replied. ...(*Interruptions*)... He has replied to the debate. ...(*Interruptions*)... I want to hear the Minister of Parliamentary Affairs. ...(*Interruptions*)..

SHRI ANANTHKUMAR: Hon. Chairman, Sir, let the Motion of Thanks on the President's Address be commended to the House. ...(*Interruptions*)... Let it be put to vote of the House. ...(*Interruptions*)... This should not be allowed.

MR. CHAIRMAN: I think, that is enough. I shall now take up the Amendments which have been moved. ...(*Interruptions*)..

SHRI SITARAM YECHURY: We want to seek clarifications, Sir. ...(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: I am sorry. ...(*Interruptions*)..

SHRI SITARAM YECHURY: You cannot do this and be discriminatory. ...(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: I am not discriminating. ...(*Interruptions*).. Please be careful. ...(*Interruptions*).. Please be careful. ...(*Interruptions*)..

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this has never happened. ...(*Interruptions*)... This is not the precedent. It has never happened. ...(*Interruptions*)... He cannot say this to the Chair. He is casting aspersions on the Chair. ...(*Interruptions*)... Sitaram Yechury is a senior Member and what he is doing is something wrong. ...(*Interruptions*)... What he is saying is wrong. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I had asked the.. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, he is casting aspersions on the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, Sitaram Yechury ji cannot impute motive on the Chair. ...(*Interruptions*)... Your ruling is final. ...(*Interruptions*)...You have already started it now. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...(*Interruptions*)... One minute, please. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादवः सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Sharad ji, one minute. ...(*Interruptions*)... I have watched with much distress what has happened this afternoon in the House. I am not putting blame on anybody because if you look at it in totality, all the Members of the House have to share the blame in some measure or the other. I think, the normal practice, to my understanding, has been that when a speaker has the floor and somebody wishes to intervene, the person speaking concedes. Now, that has happened very often. That is a known practice. Today, different people wanted to intervene somewhere. The hon. speaker, at that moment of time, did not concede. Now, the practice is, if it is not conceded, it is not conceded. You can draw conclusions as to why it was not conceded, whether it was in keeping with parliamentary etiquette, etc. etc.

SHRI DEREK O'BRIEN: That is what we are trying to say. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, but your ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: That is what precisely we are trying to say. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I am sorry. ...(*Interruptions*)... No, no. I am sorry. ...(*Interruptions*)... It is an established practice. The debate has been conducted. Everybody has spoken. Reply has been given. Now, at the end of the reply, there is no further discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is an established practice of the House that the reply should be given. ...(*Interruptions*)... This is not a reply. Leave that point aside. ...(*Interruptions*)... This is not a reply. ...(*Interruptions*)... It is an established practice of the House... ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, he cannot decide the nature of the reply. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, the reply is not to satisfy him. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is an established practice of the House ...(*Interruptions*)... If somebody's name is taken, if my name is taken, the established practice is that he is given the right to respond. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Well, the established practice has not been observed today. ...(*Interruptions*)...

7.00 P.M.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you have upheld the practice all through. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Yes, I have. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, if my name has been taken, I have a right to respond. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: All I have to say, Mr. Yechury, is that the established practice of hearing you has not been conceded. ...(*Interruptions*)... That is the end of the matter. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANTHKUMAR: We have debated for four days, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you have yourself observed ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, this is an established practice. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Can I now take up the Amendments, please? ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादवः सभापति जी, जब मैं खड़ा हुआ था, उस समय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आप बैठिए, आपकी बात को सुनेंगे।

श्री सभापतिः हां, यह कहा था। This is on record. ..(*Interruptions*)..

श्री शरद यादवः मैं वही बात कहना चाहता हूं कि क्यों इतने परेशान हैं? **...(व्यवधान)...** मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। वह देश की बाबत है। हिन्दुस्तान में किसानों की बाबत प्रधान मंत्री जी ने बोला। मेरा यह कहना है कि इम्पोर्ट जो है **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Sharad*ji*, let me take up the Amendments. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद यादवः गेहूं और दाल का जो इम्पोर्ट है**...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: I think we have had enough discussion. ...(*Interruptions*)...

श्री अनंत कुमारः सर, आपने उन्हें allow नहीं किया, फिर वह रिकॉर्ड पर कैसे जा रहा है? **...(व्यवधान)...**

श्री शरद यादवः *

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... शरद जी, आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** Mr. Raja, please. ..(*Interruptions*).. I shall now put the Amendments which have been moved to vote. Amendment (Nos. 1 to 78) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. He is absent.

The Amendment (Nos.1 to 78) were negatived.

---

* Not recorded.

श्री शरद यादवः सर, मुझे अफसोस है कि मेरा नाम लेने के बाद आप आगे बढ़ गए।

श्री सभापतिः शरद जी ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था।

श्री सभापतिः कहा था, सही है। ...(**व्यवधान**)... सही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरीः सर, यह ज्यादती हो रही है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Sharad*ji*, please.

श्री अनंत कुमारः आपने प्रक्रिया शुरू कर दी। ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरीः आपने खुद इसको establish किया है, आप यह कैसे कर सकते हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Now, I am taking up the Amendment (Nos. 79 to 80). Shrimati Chhaya Verma is absent.

The Amendments (Nos. 79 to 80) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the Amendment (Nos. 81 to 89) by Shri Yechury. Are you moving the Amendments?

SHRI SITARAM YECHURY: I am moving them. Do I have the right to say something?

MR. CHAIRMAN: Yes, please do. Are you moving the Amendments?

SHRI SITARAM YECHURY: Yes; I have the right.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: No, Sir. Only voting ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Are you moving the Amendments?

SHRI SITARAM YECHURY: I have the right to say. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Just a minute. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, after the debate, there is voting. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Just a minute, please.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I have moved these Amendments. I am insisting on these Amendments primarily because we think that this Government, माननीय प्रधान मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, वे इतना कह दें। आप इतने बेरहम न होइए। जितने लोग लाइन में खड़े होकर मरे हैं, वे अपने खुद के पैसे बैंकों से निकालने के लिए गए थे, आप उन लोगों के बारे में चिंता तो प्रकट कीजिए – मुआवजा देने की बात छोड़िए।

श्री एम.वेंकैया नायडुः वह हमने कर दी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरीः इस स्पीच में वह नहीं है। हम चाहते हैं कि उसे जोड़ा जाए।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

श्री सीताराम येचुरीः हम समझते हैं कि आपने जितना उत्तर हमें दिया, उसके अंदर जो दिक्कतें हमने कहीं, उन दिक्कतों को ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANANTHKUMAR: Mr. Deputy Chairman, Sir, ...(*Interruptions*)... is he moving the Amendments or not? ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I have been permitted by the Chair. Let me complete.

SHRI ANANTHKUMAR: Because voting is on, Sir, ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, let me complete. I have been permitted by the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANTHKUMAR: There is no scope for any explanation. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That is wrong, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: I am only saying, Sir, that the Amendments that I have moved are connected with the actual day-today living conditions of the people that have been affected by this demonetization. The answer to that has not come. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, are you moving?

SHRI SITARAM YECHURY: It was more, keeping the UP elections in mind, an election speech. The answer to the debate has not come. So, therefore, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you insisting?

SHRI SITARAM YECHURY: I am insisting on these Amendments, and particularly the Amendment No. 81.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, the Amendment (Nos. 81 to 89) are the Amendments given by you. Out of which, you are insisting only on the Amendment No. 81.

SHRI SITARAM YECHURY: No, no; I want all of them. You put them to vote.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. That means, Mr. Sitaram Yechury is insisting on Amendments (Nos. 81 to 89). So, I am only requesting. You are not withdrawing. Are you withdrawing?

SHRI SITARAM YECHURY: No, no.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not withdrawing. Therefore, I shall put the Amendments to vote. I shall now put the Amendments (Nos. 81 to 89) moved by Shri Sitaram Yechury to vote. The question is:–

81. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret at that there is no mention in the Address about condoling or noting the tragic death of over 100 people and announcing adequate compensation to the families of those who lost their lives while standing in queue to withdraw their own hard earned money from banks/ATMs."

82. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about what did we get from the note demonetization.

83. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address that how much black money was recovered from the note demonetization."

84. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the severe drought situation faced by the States of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, parts of Telangana and Andhra Pradesh and Union Territory of Puducherry."

85. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the growing economic burden on the people, whether the industrial manufacturing production has shown a decline, the energy sector is in crisis indicating significant industrial slow down, rising unemployment, agrarian crisis is deepening, vast section of people are deprived of even meagre relief through legal entitlement."

86. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the unprecedented rise in the prices of all essential commodities."

87. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the abnormal

increase in the prices of petrol and diesel causing much hardship to the people."

88. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about empowerment of backward communities, minorities, scheduled castes, scheduled tribes and women in the country."

89. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about any effective step for making public distribution system universal, effective and people oriented."

The Amendment (Nos. 81 to 89) were negatived.

SHRI SITARAM YECHURY: If I want a division, Sir? ...(*Interruptions*)... I have the right.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you have the right. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: After it is negatived ...(*Interruptions*)... He has already ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have the right. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: I have the right unless you are denying me that also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; I will not deny.

SHRI SITARAM YECHURY: You had denied me the right to reply when my name was taken. ..(*Interruptions*).. You had denied me the right to reply when my party's policies were taken. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is over. Don't say that now. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: You had denied me that right. Unless you want to deny me this right also ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I am not denying you any right. You have got the right to insist. It is up to you.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am requesting the Government, मैं उनसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि इतने बेरहम न हों। इसको मान लें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Now, come to the amendment. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is about the amendment. इतने लोगों की जान चली गई, उनके बारे में थोड़ी सी, इतनी सी इंसानियत दिखा दो।...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Now, come to the amendment. ...(*Interruptions*)... That is okay.

श्री सीताराम येचुरीः इतनी तो इंसानियत दिखा दो कि जो लोग मरे हैं, उनके बारे में चिंता तो प्रकट करिए। I am asking this Government to accept that. If they are not going to accept that, हम कहते हैं कि हम तो यहां से वाक-आउट करके जाएंगे। अब आप चलाइए, खाली घर चलाइए। यह है जनतंत्र हमारा। अब आप हाउस को चलाइए।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

श्री शरद यादवः इस बात को मानने में क्या दिक्कत है? ...(**व्यवधान**)... इसमें क्या दिक्कत है? ...(**व्यवधान**)...लोगों के लिए condolence कर लें, तो क्या दिक्कत है? ...(**व्यवधान**)... जिन लोगों का लाइन में इंतकाल हो गया है, उनके लिए condolence करने में क्या दिक्कत है? ...(**व्यवधान**)... इसमें क्या दिक्कत है? ...(**व्यवधान**)... हम भी सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We now come to Amendment Nos. 90 to 97 by Shri Vijayasai Reddy. Shri Reddy, are you withdrawing your amendments?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh: I request your good self to allow me to say a few words about the amendments which I have moved. The hon. Prime Minister is present in the House. I request your good self to permit me to say a few words about the amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You can say what your amendment is. That I would accept.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, let me say something about it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not something! No, no. ...(*Interruptions*).... If you want, you can explain your amendment. That is all.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, after that I would like to say something.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Nothing after that. ...(*Interruptions*)... No, no. Let me tell you this; I asked you whether you were withdrawing your amendments or not. Before withdrawing, you may, if you want, say what your amendment is. I have no problem with that.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I know very well that even if my amendments are put to vote, they are not going to be passed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no time for a discussion like this.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, let me say it just in one sentence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You say what your rationale is and whether you are withdrawing your amendment. You say that.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the hon. Prime Minister is here. I would like to say a few words before him. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I have no time to argue like this! I asked you to speak. What are you doing? I told you, you may explain if you want instead of wasting my time. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, if you permit me to speak… ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this 'permit me' again? ...(*Interruptions*)… I shall now put the Amendments (Nos. 90 to 97) by Shri V. Vijayasai Reddy to vote.

90. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address fails to mention about the grant of Special Category status to the residuary State of Andhra Pradesh in spite of the fact that the assurance was given by the then Prime Minister on the floor of Parliament on 20th February, 2014."

91. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to fulfill the assurance given to the successor or State of Andhra Pradesh that package for backward areas would be given on the lines of Bundelkhand area and KBK districts in Odisha."

92. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address fails to Address the anomalies under sections 50, 51 and 56 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 that relate to recovery of arrears of taxes or duty on property, including arrears of land revenue."

93. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention about the commitment of the Indian Railways, as mandated in paragraph under the head Infrastructure', of Thirteenth Schedule to the Andhra Pradesh Reorgarrisation Act, 2014, to establish a new Railway Zone in the successor State of Andhra Pradesh with Vishakhapatnam as the Zonal Headquarter."

94. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address. does not mention about the time frame to complete the Polavaram National Project in Andhra Pradesh."

95. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address fails to mention-about setting up of a separate High Court for the State of Andhra Pradesh in a time-bound manner."

96. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address fails to mentions how and by when Government is going to divide 107 common institutions between AP and Telangana listed under Schedule X to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 20l4."

97. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention that the Government is committed to securing greater participation of women in the Parliament and State

[*Amendments (Nos. 90 to 97) were negatived*]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up Amendment (Nos. 98 to 121) by Shri D. Raja. Are you withdrawing your Amendments, Mr. Raja?

SHRI D. RAJA: Sir, I am not withdrawing, but as a Member, I wish to make some observations.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I told you, you may speak about the Amendments.

SHRI D. RAJA: No, Sir. I listened to the hon. Prime Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I said. You may speak about the amendments. I am allowing you. Start speaking.

SHRI D. RAJA: Sir, the Prime Minister spoke about the banking sector and the RBI in detail, but he did not say anything about willful default. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Talk about the Amendments. ...(*Interruptions*)..

SHRI D. RAJA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You speak about your Amendments.

SHRI D. RAJA: *

* Not recorded as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I am not allowing that. That will not go on record. ...(*Interruptions*).. That will not go on record. ...(*Interruptions*)... Mr. Raja, are you moving the Amendments?

SHRI D. RAJA: Sir, I press for voting on the Amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (Nos. 98 to 121) by Shri D. Raja, to vote.

98. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing incidents of atrocities on people of *Dalit* communities in the country."

99. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention about the need to repeal the archaic sedition law which is not needed in the democratic India."

100. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of attempt to take away the land rights of tribals given under the Forest Rights Act to facilitate coal mining in certain tribal villages."

101. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention the need to enact a central legislation for the welfare and security of the agricultural workers in the country."

102. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the attempts being made by the government to curtail trade union rights of the workers in the name of" ease of doing business."

103. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the prevailing crisis in the agriculture sector and increasing incidents of farmers committing suidide in the country."

104. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not express its concern over the abnormal increase in the Non-Performing Assets (NPAs) of the public sector Banks and Writing off a total ₹ 1.14 akh crore of bad debts between the financial years 2013 to 2015."

105. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the continuous slow down in the growth rate of economy."

106. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the continuous decline in India's export during the last 15 months."

107. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not express its serious concern over the delay in passing the legislation on reservation of women in the Parliament and State Assemblies."

108. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the deteriorating quality of education particularly at the higher level in the country."

109. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing commercialization of education sector making it impossible to get quality education to the common people."

110. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the deteriorating condition of the public health facilities in the country compelling the poor patients to avail medical treatment from costly private medical institutions."

111. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not express its concern over the increasing incidents of crime against women and children in the country."

112. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to solve the problem of unemployment particularly of the educated youth in the country."

113. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention about the need to pay sustainable wages to the Anganvadi and Asha workers in the country."

114. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the increased attacks on the tribal people in the country particularly in Chhattisgarh."

115. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the fact that the decision of demonetization of currency notes of ₹ 500 and ₹ 1000 denominations pushed the economy as well as the common people into a distressful condition."

116. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not take note of the fact that certain right wing forces in the country are trying to destroy the secular-democratic fabric of the country by attacking the Universities, all educational and cultural institutions, freedom of speech, right to dissent, minorities, *dalits*, tribals and progressive activists."

117. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not express its concerrn over the diversion of all cations made for sub-plans for SCs and STs."

118. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does mention about the increasing number of derailments of trains due to deterioration of safety standards of the Indian Railways and ignoring the recommendations of various reports on accidents in the Railways."

119. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention about the continued protest of the Ex-service men demanding full implementation of the One Rank, One Pension (OROP). "

120. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

"but regret that the Address does not mention about the fact that thousands of villages still remain without electricity in the country."

121. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:–

‘‘but regret that the Address does not mention about the fact that ₹ 653 crore scheme for safety of women on public transport and ₹ 79.6 crore Nirbhaya project devised in the year 2015-16 for the safety or women still remain unutilized whereas the attacks on women goes on unchecked.’’

The Amendment (Nos. 98 to 121) were negatived.

SHRI D. RAJA: Sir, you should allow Members to ask questions. You are not allowing.. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I said.

SHRI D. RAJA: Sir, the Prime Minister is willing to concede. Let him say it. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, listen, Mr. Raja. You are a very senior Member. I was communicating in English. I said, you can speak about your Amendments; you can explain your Amendments. I said that to Mr. Reddy too. But you are not doing that. You are making a speech. That I cannot allow.

SHRI D. RAJA: No, Sir. It is not a speech. It is an explanation. You should have allowed me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I said. You didn't explain.

SHRI D. RAJA: No, you didn't… ...(*Interruptions*)... That is what I was trying to explain.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You didn't explain.

SHRI D. RAJA: No, no. I tried to explain what the Prime Minister failed to address. So, I am walking out, as a Member of the CPI.

(*At this stage, the hon. Member, left the Chamber*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. V. Vijayasai Reddy, you are a new Member. You should know. You please listen to me. I have no objection if you had explained about the Amendment. I allowed you that. You did not do that. I allowed Mr. D. Raja also. But instead of doing that, you started making a lecture.

Now, Amendment Nos. 122 to 186 are moved by Shri Ritabrata Banerjee. He is absent. I believe, these Amendments were moved earlier. Therefore, they have to be put to vote. They have already been moved.

I shall now put the Amendment Nos. 122 to 186 to vote.

The Amendment (Nos. 122 to 186) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment Nos. 187 to 545 by Shri Sanjay Seth. He is absent. But, they were moved earlier. I think, they were moved earlier. Now, I shall put the Amendment Nos. 187 to 545, moved by Shri Sanjay Seth, to vote.

The Amendment (Nos. 187 to 545) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 643 and 644 are moved by Shri Derek O'Brien. Are you moving your Amendments?

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, I am not giving a speech. Allow me to read the Amendment. I read the Amendment.

> "The Address fails to pay respect to the 120 plus lives lost due to demonetisation and the hardship faced by farmers, textiles, construction and plantation workers, small business owners, trading communities, fishermen, housewives, students and large sections of the middle class."

Sir, I would request this Government that even if we don't vote on this, stand for one minute silence, at least, for these people…(*Interruptions*)… Don't laugh. I am requesting you to stand for one minute silence and you are laughing about it. I am disappointed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Derekji, there is no Amendment.

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, there is another Amendment on the withdrawal limit. The withdrawal limit has still not been lifted. I am requesting for one minute silence and they are laughing at it. The Prime Minister has not mentioned anything in his speech. What are we doing? Plastic we eat, plastic for lunch and dinner. हम लोग प्लास्टिक खाएंगे? प्लास्टिक से पेट भरेगा? So, we are walking out.

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put Amendment Nos. 643 and 644 by Shri Derek O'Brien to vote.

The Amendment (Nos. 643 and 644) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment Nos. 645 to 651 by Shri Nazir Ahmed Laway. Are you moving the Amendments?

SHRI NAZIR AHMED LAWAY (Jammu and Kashmir): No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 645 to 651 are not moved. If you have already moved the Amendments, then, the withdrawal comes.

SHRI NAZIR AHMED LAWAY: Sir, I have already moved the Amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then you say, I withdraw the Amendment (Nos. 645 to 651).

SHRI NAZIR AHMED LAWAY: Sir, I withdraw Amendment Nos. 645 to 651.

The Amendment (Nos. 645 to 651) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 645 to 651 are withdrawn. I think, all Amendments are either negatived or withdrawn. Therefore, I shall put

the motion to vote.

The question is,

"That an Address be presented to the President in the following terms:–

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2017."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at fifteen minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 9th February, 2017